

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> डॉ. अजय कौशिक को मिला...



हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का पहला दिन

पेपर लीक, प्रधान के इस्तीफे की मांग और चढ़ावा चोरी पर पेपर लीक, प्रधान के इस्तीफे की मांग और चढ़ावा चोरी पर हंगामा

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर विपक्ष के जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन मुद्दों को उठाया, जिसके कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला और ना ही कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। सदस्य दोनों सदनों में हंगामा और नारेबाजी करते रहे। लोकसभा और राज्यसभा में बार-बार के स्थगन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट यूजी पेपर लीक और चढ़ावा चोरी लिखी तख्तियां लेकर सदन के बीचोंबीच पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से जनता को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। उन्होंने तख्तियां लहराने और नारेबाजी को सदन की मर्यादा के विपरीत बताते हुए

कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। हंगामा नहीं धमने पर उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तथा असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण कार्यवाही पहले एक बजे और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

भोजनावकाश के बाद भी गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी जमदग्निबका पाल ने नियम 377 के तहत सदस्यों को अपने विषय उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य फिर तख्तियां लेकर सदन के बीचोंबीच पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने



कोरम का मुद्दा उठाया, जबकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने सांसदों को सदन में आने से रोके जाने का आरोप लगाया, जिसे पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर पहले कार्यवाही पहले तीन बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इस तरह लोकसभा में पूरे दिन कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका।

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहले नौ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इसके बाद सदन ने दिवंगत सदस्यों तथा कतर के पूर्व अमीर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन रखा गया। आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। श्री खरेगे ने कहा कि नीट यूजी पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और जंतर-मंतर पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं,

लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को कुचलने की कोशिश कर रही है। उनके इतना कहते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और सभापति ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्य पेपर लीक और जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी करते रहे। लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही दूसरी बार 12.30 बजे तक, तीसरी बार 12.50 बजे तक, चौथी बार दो बजे तक और पांचवीं बार ढाई बजे तक स्थगित करनी पड़ी। छठी बार बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सुबह से सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और सदस्यों से उच्च सदन की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी-अपनी सीटों पर लौटने तथा कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिए और सभी सदस्यों को माहौल बनाना चाहिए, लेकिन उनकी अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। लगातार नारेबाजी जारी रहने पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई और मानसून सत्र के पहले दिन सदन में कोई विधायी कार्य नहीं हुआ।



सोशल मीडिया पर साझा की गयी ज्ञापन की तस्वीर में कहा गया कि श्री प्रधान का इस्तीफा पहले दिन से सीजेपी की मांग रही है, क्योंकि वह कई पेपर लीक होने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। ज्ञापन में कहा गया, इस देश के युवाओं का मानना है कि श्री प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री के तौर पर पूरी तरह नाकाम रहे हैं। नीट 2026 समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने और दूसरी गड़बड़ियों के लिए वे सीधे

तौर पर जिम्मेदार हैं। हाल ही में सीबीएसई 12वीं के पोर्टल में गड़बड़ी और सीयूईटी परीक्षा में देरी जैसी घटनाएं भी सामने आयी हैं। नीट पेपर लीक की वजह से 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। हाल के समय में कई परीक्षाएं या तो लीक हुई हैं, उनमें देरी हुई है या तकनीकी दिक्कतें आयी हैं, लेकिन श्री प्रधान की तरफ से न तो व्यवस्था में कोई सुधार किया गया, न ही कोई कार्रवाई हुई और न ही ऐसा करने की कोई मंशा

संसद से सड़क तक बवाल-शाह ने संभाला मोर्चा, प्रधान के साथ चार घंटे बैठक

नई दिल्ली। संसद के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कारण मची अफरा-तफरी के बीच हालात सामान्य बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। संसद भवन स्थित अपने कार्यालय से वह स्थिति पर पल-पल की खबर लेते रहे और मंत्रियों के साथ लंबी मंत्रणा करते रहे। वहीं, कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी दिल्ली पुलिस आयुक्त और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख महेश दीक्षित के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की।

कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर आए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान लगभग चार घंटे तक अमित शाह के दफ्तर में बैठे रहे। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था और सोमवार को संसद तक मार्च करने का आह्वान किया था।



नीट का संबंध मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन से होने के कारण स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह से बातचीत का चैनल खोलकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत तक नहीं करने की सरकार की हठधर्मिता के विपक्ष के आरोपों की धार को कुंठ किया गया। अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के विरुद्ध

पुलिस को सख्त कार्रवाई से बचने के साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और हालात को बेकाबू होने से भी बचना भी सुनिश्चित किया। यही कारण है कि संसद के गेट पर पहुंच चुके प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर तितर-बितर किया गया, लेकिन अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रदर्शनों के बीच अफवाह फैलाकर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, लेकिन मोबाइल कॉल को चलने दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख महेश दीक्षित ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ खुफिया जानकारी साझा की और उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त बने अनुराग कुमार खुद खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक थे और 20 वर्षों से वहां काम कर रहे थे।



दुर्ग। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रभावना का विकास करना है। शिक्षा संस्कारित समाज, सशक्त राष्ट्र और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा संसाधनों या अवसरों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक अधोसंरचना, तकनीकी संसाधन और समान अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश की नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जामगांव (एम) में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026-27 को संबोधित करते हुए यह बात कही।

प्रमुख समाचार

कलकता हाई कोर्ट से ममता गुट को बड़ा झटका

कोलकाता। कलकता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को झटका दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्य पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को ईडी ने 440.42 करोड़ रुपये की राशि के साथ फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई पार्टी के कुछ बैंक खातों के माध्यम से कथित बेईमान वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में की गई जांच के सिलसिले में की गई है। मामले में पक्षों की दलीलें समाप्त होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को प्रार्थना पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने 2023 और 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नवगठित इकाई को हस्तांतरित किए। यह पाया गया कि इस इकाई को एक बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी।

अभिजीत दीपके ने खत्म की भूख हड़ताल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कहने पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी। सोनम वांगचुक अभी सफदर्जंग अस्पताल में भर्ती हैं। दीपके ने यह उपवास तब शुरू किया था जब 18 जुलाई को वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनकी 21 दिन की भूख हड़ताल के कारण उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक परीक्षा सुधारों की अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर जमा हुए। उधर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तीन कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जंतर-मंतर पर अपनी 23 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने यह कदम विपक्षी विधायकों, नागरिक समाज के सदस्यों और जानी-मानी हस्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल की अपील पर उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे संसद और जन-अभियानों के जरिए आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया था।

नीट धांधली पर ‘चलो संसद’ मार्च! उमड़ा हजारों का हुजूम

नईदिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली रणक्षेत्र में तब्दील हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के चलो संसद मार्च के आह्वान पर देश भर से आए हजारों छात्र और युवा प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर जमा हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़पें देखने को मिलीं, जिससे लुटियंस दिल्ली में भारी तनाव फैल गया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि उसने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया या बल प्रयोग किया। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा, मीडिया के कुछ हिस्सों ने जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा/हिरासत में लेने की छिटपुट घटनाओं का जिक्र किया है। यह सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और विरोध प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है।

सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर डीएमके विधायक गिरफ्तार

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कणगम (डीएमके) के विधायक जी.वी. मार्कंडयन को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने हाल ही में एक जनसभा के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जे.सेफ विजय के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी बातें कही थीं। तीन बार विधायक रह चुके मार्कंडयन को पुलिस ने थूथुकुडी जिले में उनके घर से हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला सत्ताधारी पार्टी तमिलनाा वेटी कन्नम (टीवीके) के एक पदाधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विधायक ने 18 जुलाई को कोविलपट्टी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी बातें कहीं।

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बचाने असदुद्दीन औवैसी लामबंद

नईदिल्ली। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन औवैसी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के प्रस्तावित कदम की आलोचना की और इसे मुस्लिम शिक्षा पर हमला बताया। सहारनपुर के दौरे के दौरान औवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़ी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला सिर्फ एक शिक्षण संस्थान का नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक प्रगति का है। शिक्षा से जुड़े आंकड़ों का जिक्र करते हुए औवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 19-20% है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3.5-3.7% ही ग्रेजुएट हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में मुसलमानों की साक्षरता दर लगभग 53-54% है, और मुस्लिम महिलाओं में यह दर और भी कम है। उन्होंने कहा कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें गिरा दी गईं, तो हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। औवैसी ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी में लगभग 3,000 छात्र पढ़ रहे हैं।



संसद का मानसून सत्र: हंगामे नहीं, समाधान का संकल्प बने

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल उसकी संसद है। यही वह मंच है जहां देश की आकांक्षाएं, समस्याएं और भविष्य की दिशा तय होती है। संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, जवाबदेही और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। ऐसे में 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा संसद का मानसून सत्र केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता की नई परीक्षा भी है। देश की जनता की अपेक्षा है कि यह सत्र शोर-शराबे, आरोप-प्रत्यारोप और गतिरोध का नहीं, बल्कि सार्थक संवाद, गंभीर बहस और ठोस निर्णयों का सत्र बने। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में संसद के दृश्य लोकतांत्रिक गरिमा की अपेक्षा राजनीतिक टकराव

के प्रतीक अधिक दिखाई दिए हैं। सदन में नीति और नीयत पर चर्चा कम तथा नारे, तख्तियां, वेल में प्रदर्शन और कार्यवाही बाधित करने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती रही है। संसद का प्रत्येक मिनट जनता के कर से चलता है, इसलिए उसका अनुत्पादक होना केवल संसदीय विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संसाधनों का भी दुरुपयोग है। संसद का उद्देश्य सरकार को घेरना अवश्य है, लेकिन केवल हंगामा खड़ा करना नहीं; उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल बहुमत के बल पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि विपक्ष की बात सुनना और संवाद के लिए वातावरण बनाना भी है।

इस बार विपक्ष के पास अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर वह सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रतियोगी परीक्षाओं में

कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, सीमा सुरक्षा, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद, मन्दिरों में चोरी, कर व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया जैसे विषय निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन पर संसद में गंभीर चर्चा होना लोकतंत्र की आवश्यकता भी है और जनता का अधिकार भी। लेकिन यदि ये विषय केवल राजनीतिक नारेबाजी का माध्यम बनकर रह जाएं, तो उनका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। संसद में उठाना गया प्रत्येक मुद्दा समाधान की दिशा में बढ़े, यही लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण होगा। संसद को राजनीतिक षड्यंत्र मानकर संवाद से वंचित कर दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र का अविनाश संकेत है। उसका दायित्व केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को



बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना भी है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की आंख और कान दोनों होता है। यदि वह केवल विरोध की राजनीति तक सीमित हो जाए, तो उसकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर सरकार भी यदि विपक्ष के प्रत्येक प्रश्न को राजनीतिक षड्यंत्र मानकर संवाद से बचती है, तो लोकतंत्र का संतुलन कमजोर पड़ता है। इसलिए सत्ता और विपक्ष, दोनों को अपने-अपने दायित्वों

का गंभीरता से निर्वहन करना होगा।

मानसून सत्र में यदि शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होती है तो उसका केंद्र छात्रों का भविष्य होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ। यदि महंगाई पर बहस हो तो उसका उद्देश्य आम नागरिक को राहत देने वाली नीतियों पर विचार होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति अथवा सीमा संबंधी विषय उठते हैं तो उनमें दलगत राजनीति के बजाय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। संसद की बहस तब सार्थक कही जाएगी, जब उससे नीति निर्माण की दिशा निकले और जनता को यह विश्वास हो कि उसकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार हो रहा है। लोकतंत्र में बहस और असहमति

कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। किंतु जब असहमति का स्थान अवरोध ले लेता है और बहस की जगह बहिष्कार आ जाता है, तब लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि संसद को चलाना ही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी है। यह विचार आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। संसद का ठप होना किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है।

इस समय देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवाओं को रोजगार तब सार्थक कही जाएगी, जब उससे नीति निर्माण की दिशा निकले और जनता को यह विश्वास हो कि उसकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार हो रहा है। लोकतंत्र में बहस और असहमति

अपनी विकास गति बनाए रखनी है। ऐसे समय संसद से जनता समाधान चाहती है, संघर्ष नहीं। यदि पूरा सत्र केवल राजनीतिक टकराव में बीत गया तो सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होगा, जिसकी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। संसद की गरिमा केवल अध्यक्ष की कुर्सी या ऐतिहासिक भवन से नहीं बनती, बल्कि वहां बैठने वाले जनप्रतिनिधियों के आचरण से बनती है। सांसदों को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे केवल अपने दल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद में उनका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक व्यवहार लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा बनता है। इसलिए व्यक्तिगत आरोपों और कटुता के स्थान पर तथ्यों, तर्कों और नीति आधारित विमर्श को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भू-विस्थापितों ने एसईसीएल प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। सोमवार को एसईसीएल मानिकपुर क्षेत्र के खदान विस्तार से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसईसीएल मानिकपुर प्रभावित ग्राम भू-विस्थापित समिति ने 20 जुलाई को महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है।

समिति ने चेतावनी दी है कि मांगों न मानी जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इस समिति में मिलाई खुर्द, रापाघर्रा, कुदारी खार, दादर खुर्द सहित 10 गांवों के ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मानिकपुर खदान विस्तार के समय उनकी भूमि अधिग्रहीत की गई। यह उपजाऊ और सिंचाई युक्त भूमि नाला डायवर्सन के नाम पर ली गई थी। अब उनके मकान और खेती योग्य जमीन भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। रोजगार के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं। जमीन जाने के बाद ग्रामीणों के पास जीविका का कोई साधन नहीं बचा है। वर्षों से दिए जा रहे आश्वासन



15 दिन में कार्टवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी

जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए हैं। ग्रामीणों ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। सभी निजी ठेका कंपनियों में प्रभावित गांवों के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। योग्यतानुसार जमा आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जाए। हस्त्यजैसी निजी कंपनियों को दलाली या पैसों की मांग न करने का निर्देश

दिया जाए। पहले कलिंगा कंपनी के समय हुए छलावे को दोहराना न जाए।

भर्ती प्रक्रिया में भू-विस्थापित समिति का हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। छत्तीसगढ़ में स्थष्ट्ररु की खदानों में 90 फीसदी स्थानीय भू-विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण मिले।

ग्रामीणों ने कहा कि दादर खुर्द के करीब 100 किसानों की जमीन पौधारोपण के बदले रोजगार के वादे पर ली गई थी, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। समिति ने 15 दिनों में ठोस निर्णय न होने पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा, अनुविभागीय अधिकारी कोरबा और मुख्य महाप्रबंधक कोरबा को भी भेजी गई है।

सोनम वांगचुक के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन



मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के फिरोशर में आज भारतीय किसान यूनियन (टिक्कै) के नेतृत्व में सोनम वांगचुक के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार फिरोशर को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक के

लोकतांत्रिक आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया है। साथ ही नोट सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की गई।

भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि शिक्षा का बढ़ता बाजारीकरण, छात्रों के भविष्य और देश के हित में गंभीर चिंता का विषय है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं।

कचरे के ढेर में मिले छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व जनप्रतिनिधियों के तैलचित्र

लोरमी। मुंगेला जिले के लोरमी नगर पालिका क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व जनप्रतिनिधियों के तैलचित्र कथित तौर पर कचरे के ढेर में फेंके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना सामने आने के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इसे राजनीतिक विद्वेष से जुड़ी हरकत बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए अज्ञात अस्माजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अज्ञात लोगों ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते छत्तीसगढ़ महतारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया के गरिमामयी



तैलचित्रों को कचरे के ढेर में फेंक दिया। कांग्रेस का कहना है कि घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्रवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। भौगोलिकसंदर्भकांग्रेस ने पुलिस से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनकी पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पार्टी का आरोप है कि इस तरह की हरकत समाज में वैमनस्य और तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश है।इधर, मामले को

समय से पहले नाबालिग दुल्हा-दुल्हन की शादी पुलिस ने रोकी



कोरबा। कोरबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की और 15 साल के लड़के की शादी कराई जा रही थी। ऐन वक्त पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और मानिकपुर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाह को रूकवा दिया। जानकारी के मुताबिक, चिमनीभटा बाई नम्बर 14 में रहने वाले 15 साल का नाबालिग दूल्हा और 13 साल की दुल्हन एक-दूसरे को पसंद करते थे। दोनों की जिद के आगे झुककर परिजनों ने सामाजिक रीति-रिवाज से उनकी शादी करने का फैसला कर लिया था। घर पर मंडप सज चुका था

अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से मौत, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार

जीपीएम।गौरेला थाना के दरमोहली गांव में अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने लगभग 20 दिन बाद खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक भरमार बंदूक, एक एयर गन और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक का बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर पूरे मामले को छिपाने का भी प्रयास किया है। गौरेला थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने बताया कि घटना 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार हरिश्चंद्र पनिका ने सूचना दी थी कि दरमोहली निवासी सरवन सिंह कुशराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने बताया कि सरवन की मौत पेट दर्द और खून की उल्टी



होने से हुई है, लेकिन घटनास्थल पर कमरे में खून के धब्बे मिलने से पुलिस को संदेह हुआ और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 17 जुलाई को मृतक के बड़े भाई पवन सिंह ने पुलिस को वास्तविक घटना बताई। उसने बताया कि 27 जून को गांव के कुछ लोग उसे जंगल ले गए, जहां सरवन सिंह का शव पड़ा था। वहां मौजूद लोगों ने स्वीकार किया कि सभी लोग जंगल में जंगली जानवर का अवैध शिकार करने गए थे।

इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम द्वारा भरमार बंदूक से चलाई गई गोली सरवन सिंह के सीने में लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और पुलिस को जानकारी नहीं देने का दबाव बनाया। जब पवन सिंह ने विरोध किया तो उसे भी गोली मारने की धमकी दी गई।

कन्या छात्रावास में अचानक 10 से 15 छात्राएं हुई बीमार, 4 का अस्पताल में इलाज जारी

कवर्धा। जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक के बाद एक कई छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 10 से 15 छात्राओं के बीमार होने की सूचना मिली, जिससे छात्रावास प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही छात्रावास को प्रभारी अधीक्षक ने तत्काल सभी छात्राओं को उपचार के लिए प्रार्थमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद चार छात्राओं की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया रेफर कर भर्ती कराया, जबकि अन्य छात्राओं का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

प्रारंभिक तौर पर मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा माना जा रहा



है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीमार होने के कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। एहतियात के तौर पर छात्राओं की लगातार निगरानी की जा रही है।

डॉक्टरों के अनुसार सभी छात्राओं की हालत फिलहाल सामान्य है और किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्रावास पहुंचकर पूरे

मामले की जानकारी जुटाने के साथ ही भोजन एवं अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच में जुट गई है।

यह घटना पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास की है, जहां घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल देखा गया।

खुड़खुड़िया में पांच जुआ फड़ पर दबिश्, पकड़े 33 जुआरी

रायगढ़। जिले में पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़-कोरबा बॉर्डर पर खुड़खुड़िया जुआ खेल रहे 33 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मामला छाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छाल थाने की पुलिस टीम ने ग्राम धसकामुड़ा में मेला स्थल के बाहर दबिश् दी। यहां जुए के पांच फड़ संचालित हो रहे थे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 33 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों के पास से लगभग 90 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की। इसमें एक इनोवा, दो बोलेरो, दो अर्टिगा, एक किआ और एक ऑल्टो कार शामिल हैं। जुआ फड़ से 57 हजार 140 रुपये नकदी भी बरामद हुई। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने पांच गैस लाइट भी जब्त की हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए जुआरी विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं। ये घरघोड़ा, तमनार, डभरा और जैजैपुर क्षेत्र से आए थे। वे धसकामुड़ा बस्ती के छोर पर बड़े पैमाने पर खुड़खुड़िया जुआ खेल रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी और एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल ने मार्गदर्शन दिया।

टूटी एटीएम मशीन छोड़ मागे चोर, चोरी का प्रयास विफल

जगदलपुर। नगरनार थाना क्षेत्र के नगरनार चौक में स्थित एक एटीएम में बीती रात चोरी का प्रयास किया गया। अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को पूरी तरह से तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया। हालांकि, वे उसमें रखे पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाए और मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, एटीएम का कैश बॉक्स पूरी तरह सुरक्षित है। बदमाश उसे खोलने या ले जाने में कामयाब नहीं हो सके। इसी कारण वे मशीन को छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार है जब चोरों ने इस तरह एटीएम चोरी का प्रयास किया। वे इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। चोरों ने एटीएम मशीन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था।

जगदलपुर में टक्कर से वाई बॉय जमीन पर गिरा

जगदलपुर। बीती रात महिंद्रा शोरूम के आगे दो वाहनों की चपेट में आने से मेकाज में पदस्थ वाई बॉय प्रवीण बाघमारे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पताल स्टॉफ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस वाहनों की तलाश कर रही है। प्रवीण बाघमारे अपनी दुपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे थे। महिंद्रा शोरूम के पास सामने से आ रही एक चारपहिया वाहन ने उन्हें टोकर मार दी। जैसे ही प्रवीण जमीन पर गिरे, पीछे से आ रहे एक बोलेरो वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेकाज अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू अस्पताल पहुंचे और देर रात तक परिवार के साथ रहे। उन्होंने डॉक्टरों को प्रवीण के शव का जल्द पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाने वाले इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं।

ग्राम पंचायत सलका भवन में घुसा बारिश का पानी

सुरजपुर। जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्रांप सलका में बारिश ने पंचायत भवन की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है। मुख्य सड़क ऊंची बनने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पूरा पानी पंचायत भवन परिसर में भर रहा है। पहली ही बारिश में पंचायत भवन जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों के साथ-साथ पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था और गत हाईटेक पंचायत भवन की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन के सामने बनी सीसी सड़क का निर्माण भवन से ऊंचा किया गया है। ऐसे में बारिश का पानी सीधे पंचायत भवन में प्रवेश कर जाता है। स्थिति यह है कि पहली ही बारिश में भवन के अंदर पानी भर गया, जिससे पंचायत कार्यालय में रखे फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामग्री में खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्राम पंचायत सलका के सरपंच शिवकुमार अग्ररिया ने बताया कि यह पंचायत भवन वर्ष 1984 में बनाया गया था।

एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर 7 किमी तय कर पहुंचाया जिला अस्पताल

बीजापुर। जिले के उसूर विखंड के दूरस्थ ग्राम रायगुड़ा में सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में ग्रामीणों और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीज सावन मरकाम को करीब 7 किमी तक खाट पर उठाकर खेतों और कच्चे रास्तों से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से रायगुड़ा तक सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी मरीज को इस तरह खाट पर होने की नौबत ना आए। बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह घटना दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संपर्क की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। आपातकालीन स्थिति में भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाने से मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है।

तुडगे में तीन परिवारों के 17 सदस्यों ने अपनाया मूल धर्म

कांकर। कांकर जिले के अंतागढ़ के ग्राम तुडगे में रविवार को तीन परिवारों के कुल 17 सदस्यों के ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में लौटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव के गायता, पटेल, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की गई तथा सभी का सामाजिक रूप से स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में पारंपरिक विधि-विधान के साथ देवी-देवताओं की पूजा कर मूल धर्म में लौटे परिवारों का तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और शुभकामनाएं देकर अभिर्नंदन

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ स्वागत



किया गया। समाज के वरिष्ठजनों ने इस अवसर पर सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आने वाली पीढ़ियों तक इन मूल्यों को पहुंचाने की आवश्यकता बताई।

जिला पंचायत सदस्य एवं

सभापति देवेंद्र टेकाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मूल धर्म अपनाने वाले परिवारों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहना समाज की मजबूती का आधार है। उन्होंने

समाज की रीति-नीति और नियमों का पालन करते हुए आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की तथा सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम में मौजूद समाजजनों ने सामाजिक एकता, परंपराओं के सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश दिया। पूरे आयोजन के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण रहा और ग्रामीणों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा अपनी पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति देवेंद्र टेकाम सहित समाज के वरिष्ठजन, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर नौकरी से हटाया

हाईकोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट का आदेश किया निरस्त

बिलासपुर। सरकारी तंत्र की लापरवाही का मामला सामने आया है। जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकार्ड में मृत घोषित कर नौकरी से हटा दिया गया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने कमिश्नर के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट भेज दिया है।

दरअसल, जशपुर जिले के मनोरा तहसील के ग्राम गजमा निवासी मरियानुस एक्का को ग्राम पंचायत का कोटवार नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को सुबोध

कुमार तिकरी ने अनुविभागीय अधिकारी स्खरू के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे स्खरू ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, सुबोध तिकरी ने सरगुजा कमिश्नर कोर्ट में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई के बाद कमिश्नर ने 18 जून 2018 को इस अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि मरियानुस एक्का अब इस दुनिया में नहीं हैं' और उनकी कोटवार पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी। कमिश्नर आदेश को चुनौती देते हुए कोटवार मरियानुस एक्का ने हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया, कि सरगुजा कमिश्नर का आदेश पूरी तरह से गलत तथ्यों



पर आधारित है। याचिकाकर्ता जीवित है और उसी ने यह याचिका दायर की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि वह जांच कर बताए कि याचिकाकर्ता जीवित है या नहीं। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिकता केशव गुप्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता मरियानुस एक्का जीवित है। जस्टिस राकेश

मोहन पांडेय के सिंगल बेंच ने सरगुजा कमिश्नर द्वारा 18 जून 2018 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है। मामले को वापस सरगुजा कमिश्नर को भेजते हुए निर्देश दिया है कि इस मामले की दोबारा गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार सुनवाई की जाए। कोर्ट ने, सभी पक्षकारों को 19 अगस्त 2026 को सरगुजा कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होने कहा है।

शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का ही हिस्सा

प्रभु चावला

एक समय सरकारों सड़कों से उतना ही डरती थीं, जितना चुनावी मतपेटियों से। दिल्ली का रामलीला मैदान और जंतर-मंतर, मुंबई का शिवाजी पार्क और चेन्नई का मरीना बीच केवल सार्वजनिक स्थल नहीं थे। वे लोकतंत्र के ऐसे मंच थे, जहां जनता का गुस्सा राजनीतिक वैधता प्राप्त करता था। इनमें से किसी एक स्थान पर भी बड़ी सभा राष्ट्रीय विमर्श को बदल सकती थी, सरकारों को अस्थिर कर सकती थी और सत्ता में बैठे लोगों को सुनने के लिए मजबूर कर सकती थी। ये स्थल आज भी वहीं हैं। जो चीज गायब होती दिख रही है, वह है नागरिकों की उन्हें भर देने की इच्छा। परीक्षा-पत्र लीक और चुनावी मुद्दों को लेकर चला लंबा आंदोलन, जिसमें बाद में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए, एक बार फिर इस विचित्र परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कई सप्ताहों तक विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और विपक्ष के कुछ वर्गों की एकजुटता के बावजूद, यह आंदोलन उस स्वतःस्फूर्त जनभागीदारी को आकर्षित करने में संचर्ष करता रहा है, जो कभी किसी शिकायत को राष्ट्रीय आंदोलन में बदल देती थी। यह खामोशी चौंकाने वाली रही है। नागरिक समाज संकोच करता दिखा है, बुद्धिजीवी बड़े पैमाने पर दूर रहे हैं और टीवी तथा सोशल मीडिया पर नियमित आक्रोश व्यक्त करने वाले लोगों ने भी अपने गुस्से को सड़कों पर उतरकर व्यक्त करने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। क्या यह एक और आंदोलन की विफलता है? या यह भारतीय लोकतंत्र के चरित्र में आये किसी गहरे बदलाव का संकेत है? देश में ऐसे मुद्दों की कमी नहीं है, जो जनता में आक्रोश पैदा कर सकें। किसान अब भी अनिश्चितताओं की शिकायत करते हैं। युवा परीक्षा और रोजगार को लेकर चिंतित हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आते हैं। फिर भी इनमें से किसी मुद्दे ने वैसी राष्ट्रव्यापी जनसक्रियता पैदा नहीं की, जिसे पहले की पीढ़ियां लगभग स्वाभाविक मानती थीं। जब सार्वजनिक असंतोष अन्य सभी क्षेत्रों में जीवित दिखाई देता है, तब सड़कों खामोश क्यों हैं? क्या असहमित सार्वजनिक चौक-चौराहों से निकलकर डिजिटल स्क्रीन पर पहुंच गयी है? या भारत ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां लोकतंत्र का संचालन सार्वजनिक विमर्श की बजाय चुनावों और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक होने लगा है? तकनीक ने निःसंदेह राजनीति की भाषा बदल दी है। पहले की पीढ़ियां बैनर लेकर मार्च करती थीं, आज की पीढ़ी स्मार्टफोन लेकर चलती है। एक हैशटैग किसी जुलूस से अधिक दूर तक पहुंच सकता है और छोटा वीडियो किसी सार्वजनिक सभा से अधिक लोगों तक पहुंच जाता है। आर्थिक परिवर्तन भी इस व्यवहारगत बदलाव में योगदान दे सकता है। भारत अब शिकायतों से अधिक आकांक्षाओं वाला देश बन चुका है। बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग करियर, शिक्षा, व्यापार और आर्थिक प्रगति में व्यस्त है। आंदोलन समय लेता है, अनिश्चितता पैदा करता है और कभी-कभी टकराव को भी जन्म देता है। समृद्धि अक्सर राजनीतिक व्यवहार को संयमित करती है। पर क्या इसने संगठित सार्वजनिक कार्रवाई की प्रवृत्ति को भी कमजोर कर दिया है? युवा पीढ़ी का व्यवहार एक और पेहेली पेश करता है। वे तीव्र प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित रोजगार और भारी पेशेवर दबाव का सामना कर रहे हैं। उनके पास संगठित होने और विरोध करने के पर्याप्त कारण हैं। फिर भी विश्वविद्यालय परिसरों में वह वैचारिक उथल-पुथल शायद ही दिखाई देती है, जिसने कभी राष्ट्रीय राजनीति को आकार दिया था। लगता है, आदर्शवादी ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आगे जाह छोड़ दी है। और राजनीति लोगों को प्रेरित करने में विफल हो रही है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(३) पुराणों के जिन-जिन वर्णनों को अदूरदर्शिता के कारण चन्द कूपमण्डूक, असम्भव, नामुमकिन, सृष्टि-निगम-विरुद्ध, प्रत्यक्ष-विरुद्ध, गप्पाष्टक, गपड़े, सफेद झूठ आदि उपाधियों से निरस्तृत करने का साहस किया करते हैं- ऐसे कतिपय विषयों का सप्रणाम एवं सयौक्तिक निरूपण अवश्य करेंगे, जिससे विज्ञ पाठक पुराणों की उपयोगिता के साथ साथ पुराणों को कोसने वाले महाशायरों की मूर्खता का भी अनुमान कर सकेंगे।

जो कुछ भी लिखा है वह सर्वथा हमें जो को अंश अटपटे तथा बुद्धि वास्तव में वहाँ तक हमारे मस्तिष्क हमारा दावा है कि पुराणों में सत्य एवं विश्वास करने योग्य है। में न जंचते हुये से जान पड़ते हैं की पृहच नहीं है, अथवा पुराणोंक लाक्षणिक शब्दों का विचार करके तत्तद् विषयों की अर्थसङ्कति विठलाने की हम में क्षमता नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान खोज की

दुहाई देकर भी तद्बुविरुद्ध पौराणिक वर्णनों को झुठलाने का प्रयत्न किया जाया करता है किन्तु निश्चित ही वर्तमान खोज सिद्धान्त-सीमा तक नहीं पहुंच पाई है, वह अभी साध्य कोटि में ही मानी जाती है। अतएव आये दिन नई नई खोज हो जाने पर पहली धाराणओं में रहो-बदल होती रहती है। सो अपेक्षित अधूरी खोज के आधार पर त्रिकालदर्शी मधियों के समाधिलब्ध रहस्यों में किन्तु-परन्तु-ननु-नच का अडङ्का लगाना विचारशील व्यक्तियों का काम नहीं हो सकता। इस अध्याय में भी इस विषय संकीर्णता के कारण कोई सुस्थिर ऋम-बन्धन नहीं कर पाए, हमारी इस विवशता के लिए उदार पाठक अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसी हमें आशा है ।

भूमण्डल-विद्या

पुराणों में भूमण्डल के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह इतना विस्तृत एवं विवेकपूर्ण वर्णन है कि जिसका मनन करने से

ऋमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

सोनम वांगचुक का आंदोलन कितना जायज, क्या निकलेगा इसका नतीजा?

अजय बोकिल

जैसी की संभावना थी, वही हुआ। दिल्ली के जंतर –मंतर पर 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट), सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के पुलिस जबरन उठा ले गई और उनकी बिगड़ती हालत के मद्देनजर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने वहां जुटे प्रदर्शनकारियों को भी चलता किया।

हालांकि सोनम की जगह कांकोरच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके अब अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन फिलहाल इस आंदोलन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सोनम वांगचुक द्वारा 20 जुलाई का प्रस्तावित मार्च भी खटाई में पड़ गया है।

लहाख के मूल निवासी सोनम की सरकार से यूं तो कई मांगें हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो नीत परीक्षा में घोटाले के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफा और प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रमुख हैं। सोनम के ताजा आंदोलन के औचित्य, टाइमिंग, उसके सामाजिक राजनीतिक असर और सरकार के रवैये को लेकर मोटे तौर पर दो अलग-अलग राय हैं। पहले वर्ग का मानना है कि सरकार को निष्ठुरता और बेरूखी दिखाने के बजाए सोनम की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार और संवाद करना चाहिए। क्योंकि सोनम जो कर रहे हैं, वो विरोध का गांधीवादी तरीका है और लोकतंत्र में इसका समुचित सम्मान होना चाहिए।दूसरे वर्ग का मानना है कि सोनम की मांगें ऐसी नहीं हैं कि जिसकी खातिर वो अपनी जान की बाजी लगा दें। उनकी मांग मुख्य तौर पर व्यवस्था सुधार से जुड़ी हैं, उसे मनवाने और सरकार पर समुचित दबाव बनाने के लिए अनशन की जगह सड़कों पर संगठित आंदोलन ज्यादा कारगर होता।वैसे भी वर्तमान सरकार ऐसे आंदोलनों के दबाव में नहीं आती। लिहाजा आमरण अनशन से निजी शोहरत और सहानुभूति तो मिल सकती है, जमीनी लाभ नैतिक समर्थन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। व्यावहारिक दृष्टि से भी सोनम के आंदोलन के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक पेंच हैं। कुछ सियासी पार्टियों ने सोनम का अब तक जबानी समर्थन किया है, तो कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शुरू से ही इसे संदेह की नजर से देखते हुए आंदोलन से दूरी बनाए हुए है। और तो और जिन युवाओं की खातिर सोनम आमरण



अनशन कर रहे हैं, उनकी रुचि भी इस आंदोलन में ज्यादा नहीं दिखती। यानी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर उनके मन में भी रोष तो है, लेकिन वह इतना भी नहीं है कि वो अपनी वर्च्युअल दुनिया छोड़कर वास्तविक दुनिया में कफन बांध कर उतर आए।

सोनम के साथ मैदानी तौर पर वो सीजेपी है, जिसका खुद का वजूद भी वर्च्युअल ही ज्यादा है। जबकि तमाम एआई और डिजिटल प्रगति के बावजूद हकीकत में जन आंदोलन सड़कों पर ही करने पड़ते हैं। उसमे भी निरंतरता चाहिए न कि जेन जी तरह एक टेम्प्रेरी इवेंट का क्रेज।

वैसे भी आंदोलनों के मामले से निपटने का मोदी सरकार का तरीका पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में काफी भिन्न है, जिस पर बहस की गुंजाइश हमेशा रही है। मसलन सरकार ने अगर किसी आंदोलन को ढील दी हो या अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हो, तो जो आगे होता है, वह राजनीतिक लाभ-हानि के तहत ही होता है। और इतनी सफाई और बेरहमी से होता है कि उन आंदोलनो का अपेक्षित चुनावी लाभ विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पाता।

बावजूद तमाम नैतिक समर्थन, सहानुभूति और संवेदनशीलता के आग्रह के, सोनम वांगचुक का आंदोलन भी उसी दिशा में जाता दिख रहा है। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट और डॉक्टरों ने भी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम की गिरती सेहत को लेकर गहरी चिंता जताते हुए उनका ध्यान रखने की हिदायत दी थी। शनिवार सुबह हुई पुलिस कार्रवाई में भी इसी को आधार बनाया गया।

पुलिस कर्मी सदै कपड़ों में पहुंचे और सोनम को उठा ले गए। हालांकि सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने पुलिस पर आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आरोप लगाया। इस कार्रवाई के एक दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया था। गौरलवब है कि जंतर मंतर पर इस आंदोलन की शुरुआत अभिजीत दिपके ने की थी और सोनम वांगचुक

इसमें 28 जून को शामिल हुए थे।

कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होने के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खी मिलने लगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि लाखों भारतीय छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे युवाओं के आंदोलन को वांगचुक की भूख हड़ताल से नई गति मिली है।

इसी अखबार को दिए इंटरव्यू में सोनम ने कहा कि सीजेपी का आंदोलन उस संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने अपनी युवावस्था में शुरू किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि ‘आमरण अनशन के दौरान सोनम का वजन साढ़े 9 किलो तक कम हो गया है। लिहाजा कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओंऔर कलाकारों ने सोनम से अनशन समाप्त करने की अपील भी की।

जहां तक सोनम के वर्तमान आंदोलन की बात है तो उसको लेकर कई सवाल हैं। पहला तो यह कि सोनम केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से जो इस्तीफा मांग रहे हैं, वह राजनीतिक मांग है। सो सरकार शायद ही माने। उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक बंद करने और व्यवस्थाओं को पुछ्छा बनाने की मांग जायज है, लेकिन जिस ‘नीट’ यूजी के संदर्भ में वो ये मांग कर रहे हैं, उसकी तो पुनःपरीक्षा भी हो गई तथा रिजल्ट भी घोषित हो गया।रीएग्जाम में व्यवस्थाएं पुछ्छा रहीं और नतीजों को सभी ने स्वीकार किया। साथ ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ऑन लाइन मार्किंग को लेकर हुआ विवाद भी हल हो गया है। ऐसे में दूसरी मांग का महत्व केवल सैद्धांतिक ही रह जाता है।

इसी तरह देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं जैसे स्थायी मुद्दे हैं, लेकिन उनको लेकर भी कोई बड़ा आंदोलन (किसान आंदोलन छोड़ दें) तो अत्रा आंदोलन के बाद बीते डेढ़ दशक में खड़ा नहीं हो सका है। दूसरे, पेपर लीक मामले के भुक्त भोगी युवा भी अगर सोनम के आंदोलन से ज्यादा नहीं जुड़ रहे तो इस आंदोलन के औचित्य पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे भी आज के जमाने में किसी भी मुद्दे पर युवाओं को सड़कों तक खींच लाना शिव धनुष उठाने जैसी चुनौती है। क्योंकि युवाओं की समस्याएं भले ही जायज और पुरानी हो, लेकिन विचार और एप्रोच की दृष्टि बहुत एकाकी और आत्मकेन्द्रित है।



कोई सम्मानित स्थान निर्धारित कीजिए।’

भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, ‘वत्स! यज्ञों के भाग का विभाजन पहले ही देवताओं में हो चुका है। महर्षियों ने हविष्य और यज्ञफल देवताओं के लिए निश्चित कर दिए हैं। तुम देवताओं के बाद प्रकट हुए हो, इसलिए वैदिक यज्ञों में तुम्हारे लिए पृथक भाग निर्धारित नहीं किया जा सकता। परंतु, निराश मत हो। भविष्य में तुम्हें ऐसा गौरव प्राप्त होगा, जो अत्यंत दुर्लभ है। आगे जन्म में तुम मनुष्यों के बीच जन्म लोगे। गर्भावस्था से ही तुम्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी शरीर में रहते हुए तुम देवतुल्य सम्मान पाओगे। ब्राह्मण तुम्हारी पूजा मंत्रों, व्रतों, जपों और अरुण्डनों से करेंगे।’

श्रीहरि ने आगे कहा, ‘तुम आयुर्वेद को

व्यवस्थित करोगे और उसे आठ अंगों में विभाजित करके संसार के लिए अमूल्य ज्ञान का स्रोत बनाओगे।’

तुम्हारे द्वारा रोगियों को जीवन और स्वास्थ्य प्राप्त होगा।’ भगवान विष्णु के इन वचनों की सुनकर अब्ब अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और उनके अंतर्धान होने के बाद अपने नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे।

द्वारप युग का आगमन हुआ। उस समय काशी के राजा सुनहोत्र के पुत्र धन्व पुराप्ति की इच्छा से तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान धन्वंतरि की उपासना आरंभ की। उनकी एक ही इच्छा थी-उन्हें असाधारण गुणों से संपन्न और लोककल्याण का कार्य करने वाला पुत्र प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान धन्वंतरि प्रकट होकर बोले,

‘राजन! मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। जो वर मांगना चाहो, मांगो।’ राजा धन्व ने कहा, ‘भगवन! कृपा करके आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।’ धन्वंतरि ‘तथास्तु’ कहकर अंतर्धान हो गए।

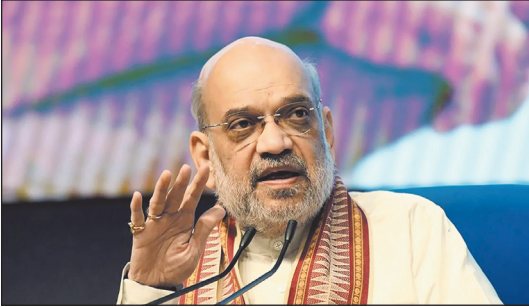
कुछ समय बाद राजा के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वह भगवान धन्वंतरि थे। बड़े होने पर उन्होंने महर्षि भारद्वाज से आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का गहन अध्ययन किया। शीघ्र ही वह इस ज्ञान में पारंगत हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि आयुर्वेद का ज्ञान विशाल और विस्तृत है। इसलिए, भगवान धन्वंतरि ने उसे व्यवस्थित करके आठ प्रमुख अंगों में विभाजित किया। उन्होंने केवल सिद्धांत ही नहीं दिए, बल्कि रोगों की पहचान, उपचार और स्वस्थ जीवन के नियम भी बताए। उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई।

आज का इतिहास

- 1865 अमेरिकी ओल्ड वेस्ट में १%क्रिक डॉ॰% गन के कुछ रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से एक में, वाइल्ड बिल हिकॉक ने डेविस टुटओवर को एक पोकर ऋण की गोली मारकर हत्या कर दी।
- 1884 पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया।
- 1888 ब्रिटेन के आक्स्फार्क डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किया जिससे परिवहन साधनों की गति बढ़ी।
- 1902 लुमिरेस फुटबॉल क्लब की स्थापना ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुई।
- 1925 अमेरिकन हाई स्कूल बायोलांजी के शिक्षक जॉन टी। स्कोप्स ने टेनेसी के बटलर एकादश का उल्लंघन करते हुए विकासवाद की शिक्षा दी।
- 1940 सोवियत संघ ने एस्टोनिया लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया।
- 1944 द्वितीय विश्व युद्ध-अमेरिकी सैनिकों ने इसे जापानी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए गुआम पर उतरा।
- 1970 मिस्स में असवान हाई डैम पूरा किया गया।
- 1973 मोसाद एजेंटों ने गलती से एक मोरको के वेंटर लिलीहैमर, नॉर्वे की हत्या कर दी, जिनके बारे में उनका मानना था कि वह 1972 के ओलंपिक हत्याकांड में शामिल थे।
- 1977 लीबिया की सेनाओं ने सह्यम में मिस्स के साथ चार दिवसीय स्पाक करते हुए एक छापा मारा।
- 1983 अंटार्कटिका के वोस्टॉक में सबसे कम तापमान माइनस 89.2 डिग्री दर्ज किया गया।
- 1995 चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के उत्तर में जल की मिसाइलें दागनी शुरू कर दीं, तीसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस शुरू किया।
- 2007 हेरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, जे। के। राउलिंग द्वारा अलोकप्रिय हेरी पॉटर श्रृंखला की अंतिम पुस्तक, इसके पहले 24 घंटों में 15 मिलियन प्रतियों के रिकॉर्ड के लिए एका की गई, जिसने इसे इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाली पुस्तक बना दिया।
- 2008 राडोवन कार्डजिंक को 12 साल की युद्धबंदी के बाद युद्ध अपराधों में गिरफ्तार किया गया।
- 2010 अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, कथित परमाणु हथियार महत्वाकांक्षाओं को रोकने की अपनी कोशिश को जारी रखा है।
- 2011 ईरान में, सेंट्रल बैंक ऑफ़ ईरान ने एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसका उपयोग ईरानियों को योजनाबद्ध आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय मुद्रा को बदलने में करने के लिए करेगा।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या की उलटी गिनती शुरू

नौरज कुमार दुवे



हिरासत में लिया था। दस्तावेजों की जांच में उनके भारत में अवैध रूप से रहने की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच नई दिल्ली से मालदा टाउन एक्सप्रेस के जरिए पश्चिम बंगाल भेज दिया गया, जहां से उन्हें सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों को सौंपकर बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अभियान के लिए 23 पुलिसकर्मियों की विशेष एस्कॉर्ट टीम तैनात की गई। पकड़े गए अधिकांश लोग गुरुग्राम में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और किराये के मकानों में रह रहे थे।

हम आपको यह भी बता दें कि गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई केवल 13 लोगों तक सीमित नहीं है। पूरे शहर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कॉलोनियाँ, झुग्गी बस्तियाँ, लेबर कॉलोनियाँ, औद्योगिक क्षेत्रों और किराये के मकानों में रह रहे 1200 से अधिक संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच जारी है। जिन राज्यों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वहां के जिला प्रशासन से सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध किरायेदार, घरेलू सहायक, होटल कर्मचारी, निर्माण मजदूर या अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहा हो तो तुरंत डायल-112 या नजदीकी थाने में सूचना दें। यह अभियान बताता है कि अब केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी अवैध नेटवर्क को तोड़ने की

रणनीति अपनाई जा रही है। हरियाणा के बाद कर्नाटक के मंगलूरु में भी इसी तरह की कार्रवाई सामने आई है। यहां पुलिस ने दो अलग-अलग निर्माण स्थलों से 11 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (स्त्रक्रह्म) को उनकी रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि उन्हें हिरासत में लेकर निर्वीसित किया जा सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल से इन लोगों को काम दिलाने वाले बिचौलिये के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि जांच अब केवल घुसपैठियों तक सीमित नहीं बल्कि उन्हें रोजगार दिलाने और देशभर में बसाने वाले पूरे नेटवर्क तक पहुंच रही है।

इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्हें विदेशी अंशदान (स्त्रष्ट्रक्र) के तहत धन प्राप्त होता था, कथित तौर पर विदेशी फंड का इस्तेमाल अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि हवाला, म्यूल अकाउंट और कई जैतों वाले बैंक लेन-देन के जरिए छोटी-छोटी रकम परसे 6 हजार, 8 हजार और 10 हजार रुपये, घुसपैठियों तक पहुंचाई जाती थी ताकि वे भारत में आर्थिक रूप से स्थापित हो सकें।

ईडी की जांच के अनुसार यह संगठित गिरोह केवल लोगों को सीमा पार कराने तक सीमित नहीं था। उनके लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य भारतीय पहचान पत्र तैयार कराए जाते थे। इसके बाद उन्हें अलग-अलग राज्यों में रोजगार दिलाया जाता था और कुछ मामलों में ई-रिक्शा, नकद सहायता तथा अन्य आर्थिक सुधारों के भीतर भी अवैध नेटवर्क को तोड़ने की

भोजशाला और ज्ञानवापी का नजराना देकर नजीर पेश करे मुस्लिम समाज

डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

दो अंग्रेजी कहान्ते हैं "The eyes are useless when the mind is blind" अर्थात् आँखें निरर्थक यदि दिमाग ही सत्य को देखने से इनकार कर दे। और दूजी कहावत है, "Flogging a dead horse" अर्थात् मरे हुए घोड़े को चाबुक मार-मारकर उससे उठने की आशा रखना। ये दोनों ही कहावतें वर्तमान समय में ‘ भारतीय मुस्लिम समाज’ पर सटीक बैठती हैं।

धार की वाग्देवी (मां सरस्वती) की पावन धरोहर भोजशाला और साथ-साथ काशीनाथ के ज्ञानवापी मंदिर का मामला आज पुन: मुस्लिम समाज से सौहाद्र की आशा लिए खड़ा है। मुस्लिम समाज और विशेषत: इस समाज के नेतृत्व का दावा करने वाले नेताओं को क्या यह बात समझ नहीं आती है कि – इस ऐतिहासिक परिसर पर हिंदू समाज का दावा केवल आस्था पर नहीं, बल्कि अकाद्यू ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है ?

मुस्लिम समाज के नेता यदि अपनी सियासती स्वार्थों के कारण सही बात नहीं पर पा रहे हैं तो मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम स्कालर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और भोजशाला व ज्ञानवापी का नजराना थाली में सजाकर हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। यदि मुस्लिम नेता और आलिम दोनों ही ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बार-बार गंगा जमुनी तहजीब की बात हिंदू और मुस्लिम समाज

दोनों को ही बंद कर देनी चाहिए। गंगा-जमुनी तहजीब केवल जुमला नहीं है यह मुस्लिम वर्ग को सिद्ध करने का यह सर्वाधिक सटीक अवसर है।

परमार वंश के महान राजा भोज द्वारा वर्ष 1034 में निर्मित यह संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनुपम केंद्र था। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस स्थान के मूल स्वरूप को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

सर्वेक्षण के दौरान परिसर और उसके मलबे से सनातन धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं की खंडित एवं संरक्षित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें भगवान गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, माता पार्वती और वाग्देवी (सरस्वती) की अद्भुत कलाकृतियां सम्मिलित हैं। ये मूर्तियां स्पष्ट करती हैं कि यह मूल रूप से एक मंदिर परिसर था।

भोजशाला की दीवारों और स्तंभों पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए कई शिलालेख मिले हैं। इनमें संस्कृत व्याकरण (पतंजलि के सूत्र), काव्य और राजा भोज की स्तुति अंकित है। मस्जिदों में अरबी या फारसी के शिलालेख होते हैं, परंतु यहाँ देवनागरी लिपि में खुदे वैदिक मंत्र और व्याकरण के नियम इस स्थान के अकाद्यू सरस्वती कंठभरण (विद्या का मंदिर) होने की पुष्टि करते हैं।

परिसर के स्तंभों, बीम और छतों पर



नकाशीदार कमल, स्वस्तिक, कलश, शंख, कीर्तिमुख और अप्सराओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। इस्लामी वास्तुकला में जीवंत आकृतियों का अंकन पूर्णत: वर्जित है, जबकि भोजशाला के कोने-कोने में ये कलाकृतियां बिखरी पड़ी हैं, जो इसके मंदिर होने का जीवंत प्रमाण हैं।

वैज्ञानिक जांच में परिसर के भीतर प्राचीन हवन कुंड और गर्भगृह के स्पष्ट अवशेष मिले हैं। वर्तमान में जो ढांचा मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वह वास्तव में मंदिर के ही स्तंभों और सामग्री को उलट-पुलट कर तथा उन्हें क्षतिग्रस्त करके खड़ा किया गया है।

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, इस मंदिर की मूल अधिष्ठात्री देवी वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश काल में यहाँ से हटाकर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया था, जिसके आधार पर भी हिंदू समाज का यह दावा वैश्विक स्तर पर सिद्ध होता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति और गैंगस्टर राजनीति की तुलना

सनत जैन

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह रही है कि सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से होता है, न कि भय, हिंसा या दबाव के जरिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक हिंसा, दलगत संघर्ष, जांच एजेंसियों के उपयोग को लेकर उठते सवाल और मीडिया की भूमिका पर बढ़ती बहस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन चर्चाओं के केंद्र में रही है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का गढ़ माना जाता रहा है। पहले वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आती थीं, जबकि हाल के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव लगातार सुर्खियों में रहा है। चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसा, पार्टी कार्यालयों पर हमले, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं तथा विरोधी दलों के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं पर समय-समय पर अदालतों और चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों को लगातार दबाव, भय या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तब राजनीति का चरित्र लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा से हटकर शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगता है। इसी संदर्भ में कुछ आलोचक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना संगठित गिरोहों की कार्यप्रणाली से करते हैं। हालांकि यह तुलना एक राजनीतिक राय है और इसे तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। दाऊद इब्राहिम भारत का एक कुख्यात अपराधी रहा है, जिस पर संगठित अपराध, तस्करी, वसूली और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोप लगे। उसकी

कार्यप्रणाली भय, दबाव और नेटवर्क आधारित नियंत्रण पर आधारित बताई जाती रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिन्हें जनता के मतों से वैधता प्राप्त होती है। इसलिए किसी राजनीतिक दल की सीधे किसी आपराधिक गिरोह से तुलना करना एक गंभीर राजनीतिक आरोप है, जिसके समर्थन में ठोस न्यायिक या कानूनी निष्कर्ष आवश्यक होते हैं। पश्चिम बंगाल पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में हमलों तथा पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को लेकर कई बार आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि उसके कार्यकर्ता राज्य में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में भी राजनीतिक हिंसा को राज्य की गंभीर समस्या बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि हिंसा को मुद्दा केवल एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक राजनीतिक संस्कृति की चुनौती बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भी बहस का विषय बनी हुई है। सरकार समर्थक और सरकार विरोधी मीडिया जैसे शब्द अब आम राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ आलोचक मीडिया के एक हिस्से को सुपारी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं, जबकि दूसरी ओर मीडिया संस्थान अपने काम को पत्रकारिता और जनहित से प्रेरित बताते हैं। यह बहस लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिक संघर्ष संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर रहे। यदि किसी भी दल, संगठन या समूह द्वारा हिंसा, धमकी या दमन का सहारा लिया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक व्यवस्था को होता है।

हाइड्रोजन से शुरू होने जा रहा है क्लीन एनर्जी का

अभिषेक कुमार सिंह

देश में पहली बार एक स्वदेशी हाइड्रोजन प्यूल-सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है. हरियाणा राज्य के जींद-सोनीपत सेक्शन पर चलने वाली हाइड्रोजन ईंधन वाली 10 डिब्बों की यह ट्रेन बिजली की ओवरहेड लाइन या डीजल इंजन पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह 3200 एचपी क्षमता वाले हाइड्रोजन प्यूल-सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी. इसकी खासियत यह है कि यह रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करती है और उत्सर्जन के रूप में केवल पानी की भाप छोड़ती है. 75 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ने वाली यह ट्रेन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह उन क्षेत्रों के लिए एक बेहतरान्व विकल्प है जहां अभी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है.

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के बीच हाइड्रोजन एक ‘क्लीन प्यूल’ के रूप में उभरा है. पिछले करीब पांच साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध और इस साल शुरू हुए अमेरिका-ईरान जैसे भी-राजनीतिक संघर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता कितनी जोखिम भरी हो सकती है. ऐसे में ‘नेशनल हाइड्रोजन मिशन’, जिसे 2022 में घोषित किया गया था, भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन का है. चूंकि भारत के पास प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और लंबा समुद्री तट है, इसलिए सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना हमारे लिए न केवल संभव है बल्कि आर्थिक रूप से भी तर्कसंगत है.

हालांकि इस मिशन की चुनौतियां कम नहीं हैं. जैसे कि एक तथ्य यह है कि हाइड्रोजन को संग्रहित (स्टोर) करना और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) करना अभी भी एक बेहद कठिन काम है, क्योंकि यह अत्यधिक



ज्वलनशील है. दबाव डालकर इसे स्टोर करना एक मुश्किल काम है. क्योंकि अत्यंत विस्फोटक होने के कारण यह ईंधन दुर्घटना का कारण बन सकता है. लेकिन जींद में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और स्टोरेज सिस्टम इसी दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा. यह न केवल सुरक्षा मानकों को परखने का मंच है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक ‘ब्लूप्रिंट’ भी तैयार कर रहा है.

एक अन्य चुनौती हाइड्रोजन ईंधन को सस्ता करने की है. असल में, जब बात लागत और कीमत की होती है तो कोयले से चलने वाले तापीय बिजलीघर बाजी मार ले जाते हैं. कोयले से मिलने वाली बिजली सस्ती है और कोयले की उपलब्धता का भी फिलहाल कोई संकट नहीं है क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देशों में 25 साल पहले की तुलना में हजारों टन ज्यादा कोयला धरती के भीतर से निकाला जा रहा है. लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक दुनिया में ऊर्जा की मांग तीन गुना ज्यादा बढ़ जाएगी.

भारत-चीन जैसे विकासशील देशों में तो यह मांग इतनी तेजी से बढ़ेगी कि इसे पूरा करने में पसीने छूट जाएंगे. भारत को अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला

विदेशों से मंगाना पड़ता है, ऐसे में आज की सस्ती बिजली का भविष्य काफी महंगा नजर आता है क्योंकि इससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, कार्बन उत्सर्जन आला से बढ़ता है.

कोयला-संचालित ताप बिजलीघरों के बारे में ये धर्मल प्लांट अपने बराबर की क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर की तुलना में 100 गुना ज्यादा रेडियोएक्टिव पदार्थ सीधे हवा में छोड़ते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि या तो एटमी बिजली की तरफ बढ़ा जाए या फिर हाइड्रोजन ईंधन समेत स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्प आजमाए जाएं.

आज जब हम कोयला आधारित ऊर्जा की सीमाओं और जीवाश्म ईंधन के जलवायु पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं, तब परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प ही भविष्य का सहारा हैं. लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी नए ईंधन को अपनाने के लिए तकनीकी तत्परता और उपभोक्ता विश्वास का होना अनिवार्य है. एथेनॉल मिश्रण से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन तक की यह यात्रा भारत के ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन लक्ष्य (2070) को प्राप्त करने का ही हिस्सा है. हाइड्रोजन न केवल परिवहन क्षेत्र को बल्कि स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे भारी उद्योगों को भी कार्बन-मुक्त करने की क्षमता रखता है.

भारत का यह हाइड्रोजन प्रेम कोई क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि ऊर्जा स्वावलंबन और वैश्विक नेतृत्व की ओर एक सुनियोजित कदम है. आने वाले समय में जैसे-जैसे इलेक्ट्रोलाइजर की लागत कम होगी और तकनीक परिपक्व होगी, हाइड्रोजन केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी बनेगा. भविष्य का ईंधन न केवल सस्ता होना चाहिए, बल्कि वह सुरक्षित और पृथ्वी के लिए मित्रवत भी होना चाहिए, और इस पैमाने पर हाइड्रोजन सबसे खरा उतरता है.

इन तमाम वैज्ञानिक और पुरातात्विक तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि धार की भोजशाला पर हिंदू समाज का अधिकार पूरी तरह स्वाभाविक, ऐतिहासिक और न्यायसंगत है। ऐसे में, इस सत्य को नकारकर अदालतों में अपील दर अपील करना केवल समय की बर्बादी और समाज में कटुता बढ़ाने का माध्यम ही बनेगा।

काशी की ज्ञानवापी और धार की भोजशाला दोनों ही स्थानों पर प्रत्यक्ष दिखने वाले पुरातात्विक साक्ष्य चिल्ला-चिल्लाकर सच्चाई बयां कर रहे हैं। सत्य को केवल कानूनी दांव-पेंचों से कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। न्यायालय भी अंततः साक्ष्यों और जनभावनाओं के संतुलन पर ही निर्णय देता है। ऐसे में फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना अपनी ही कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है।

मुस्लिम समाज के नेताओं, मुल्ला-मौलवियों, बुद्धिजीवियों यह विचार करना ही चाहिए कि ऐसी हठधर्मिता भला किस काम की? वो क्यों अयोध्या जैसी ज़िद किए रहना चाहते हैं? हठधर्मिता का अंत हमेशा कड़वाहट के साथ होता है, जबकि संवाद का अंत सदैव सम्मान के साथ होता है।



नहीं बढ़ पाई है। पांचवीं, मानव पूंजी: शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में अभी भी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है। छठी, वैश्विक अनिश्चितताएं: भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाएँ, ऊर्जा कीमतें और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक भी विकास की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

हालाँकि, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह एक आर्थिक आकलन है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। यदि भारत अगले दो दशकों में तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगार सृजन, विनिर्माण विस्तार, बुनियादी ढाँचे में निवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो 2047 का लक्ष्य अधिक यथार्थवादी हो सकता है।

इसलिए सुरजीत भट्टा का तर्क मूलतः यह है कि यदि वर्तमान गति और संरचनात्मक चुनौतियाँ नहीं बदलीं, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 से काफी आगे खिसक सकता है। इसके पीछे प्रमुख कारण बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं- पहला, विकास दर की चुनौती: विकसित देशों की श्रेणी में पहुँचने के लिए भारत को लंबे समय तक लगभग 7-8% या उससे अधिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि बनाए रखनी होगी। यदि वृद्धि 6% के आसपास रहती है, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है।

दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कम होना : भारत की कुल

आम मुसलमानों के मन में अकारण भय पैदा करते हैं। वे यह झूठा उर् फैलाते हैं कि यदि आज एक मस्जिद छोड़ी, तो कल सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी।

मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि वह इन चंद सियासी ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इस समाज को अब आत्ममंथन करना होगा। उन्हें अपनी कमान अड़ितल रख वाले नेताओं के हाथ से छीनकर प्रतिशिली, शिश्ति और उदारवादी चेहरों को सौंपनी होगी, जो देश की मुख्यधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखते हों।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसले कानून की सीमाओं में बंधे होते हैं, लेकिन दिलों को जोड़ने का काम अदालतें नहीं कर सकतीं। धार और काशी के मामलों में यदि मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट न जाकर सीधे हिंदू समाज के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण समझौता कर ले, तो यह पूरे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति की एक अनुपम मिसाल होगी।

यह अवसर इतिहास की बदलने का है। भारतीय मुस्लिम समाज को कड़वाहट की अपनी पुरानी विरासत को यहीं दफन करना चाहिए। उसे धार व काशी में चीख-चीख कर हिंदू मंदिर होने की घोषणा करते वैज्ञानिक व पुरातात्विक साक्ष्यों को हृदय से स्वीकार कर हिंदू समाज को सम्मानपूर्वक एक नजराना देकर एक नजीर पेश करनी चाहिए।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 2075 में हासिल होगा?

कमलेश पांडे

यदि आप विकसित भारत 2047 का स्वप्न देख रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि यदि भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर, उत्पादकता और रोजगार सृजन की गति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ, तो भारत को विकसित देश बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है। बता दें कि यह कोई आधिकारिक सरकारी अनुमान नहीं है, बल्कि कतिपय अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक आर्थिक विश्लेषण पर आधारित दृष्टिकोण मात्र है, जो सत्य के निकट है या परे, यह भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर है कि इससे विपक्ष को सत्तापक्ष की खिल्ली उड़ाने का एक मौका जरूर मिल गया है।

दरअसल, इस संदर्भ में चर्चित अर्थशास्त्री सुरजीत भट्टा ने भी कहा कि यदि वर्तमान गति ऐसी ही बनी रही, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हासिल करना कठिन हो सकता है। मसलन, सुरजीत भट्टला का आशय यह है कि केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। यदि वर्तमान गति, निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन की चुनौतियाँ बनी रहें, तो भारत को विकसित देश बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने और उनके जैसे अन्य कई अर्थशास्त्रियों द्वारा उठाई जाने वाली प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं- पहली, विकास दर में कमी: विकसित भारत के लक्ष्य के लिए लंबे समय तक 8-9% या उससे अधिक वास्तविक त्रक्षक वृद्धि की आवश्यकता मानी जाती है, जबकि हाल के वर्षों में वृद्धि इससे कम रहने का अनुमान है।

दूसरी, प्रति व्यक्ति आय: विकसित देश बनने का आधार केवल कुल त्रक्षक नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी है। यदि जनसंख्या के अंुपात में आय पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ती, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है। तीसरी, रोजगार की चुनौती: आर्थिक वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बनने से आय और उपभोग दोनों प्रभावित होते हैं। चौथी, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग): जीडीपी और रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक

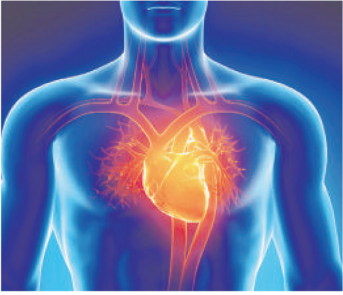
नेपाल के युवाओं में फिर से पनपने लगा है असंतोष

शोभना जैन

हाल ही में नेपाल की युवा पीढ़ी(जेनेरेशन जी) एक बार फिर सरकार की कार्यशैली से त्रस्त हो कर सड़कों पर आ गई। विडंबना यह है कि लगभग चार माह पूर्व जिस बालेन शाह सरकार को जेन-जी ने तत्कालीन ओली सरकार के खिलाफ पूरे भरोसे से व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बनाकर सत्ता तक पहुंचाया था, आज वही युवा उनके सबसे बड़े नीतिगत विरोधी बनकर सामने खड़े हैं। प्रदर्शनकारी युवा अब सीधे बालेन शाह से उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि संसद के भीतर भी विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए मंत्रियों को जनता की समस्याओं का सामना करने की नसीहत दी है। लेकिन मामला और भी गंभीर हो गया है, उनकी अपनी पार्टी में ही उनकी कार्यशैली और सरकार की नीतियों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। पारंपरिक राजनीतिक दलों से निराश युवाओं के मतदाताओं ने काटमांडू के पूर्व गवर्नर और रैपर शाह के एजेंडे की सराहना की थी। पांच मार्च को हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को भारी जनादेश भी मिला। आरएसपी के गठन के महज चार साल के भीतर पार्टी ने लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया। 27 मार्च को बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बने अभी चार महीने भी नहीं हुए हैं और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। नेपाल में एक बार फिर जेन-जी युवाओं को नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरसल यह आंदोलन केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं में बढ़ते असंतोष, पुलिसिया ज्यादाती, कथित अतिक्रमण हटाने की हालिया प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार से जवाबदेही की मांग का एक संयुक्त रूप बन चुका है। हालात इस मुकाम पर हैं कि काटमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें पिछले वर्ष इसी जेन-जी आंदोलन का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ था, अब वे खुद इसी युवा वर्ग के तीव्र विरोध और तीखे आक्रोश का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवा अब सीधे बालेन शाह से उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि

संसद के भीतर भी विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए मंत्रियों को जनता की समस्याओं का सामना करने की सीख दी है। शाह सरकार के समुख चुनौतियां काफी हैं। शाह ने अपना कार्यभार संभालते ही प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन कर सुधारों की बात कही थी लेकिन जनता का मानना है कि इन अपेक्षाओं पर सरकार पूरी तरह खरी नहीं उतरी। हाल की कुछ दुखद घटनाओं के बाद क्षुब्ध जनता का सब्र शायद जवाब दे गया और वह शाह सरकार के खिलफ सड़कों पर उतर आई तथा उनके इस्तीफे की मांग करने लगी। इससे पूर्व भी उनके कुछ फैसलों को लेकर असंतोष देखा गया था। नेपाल में ताजा विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 25 वर्षीय राइड-शेयरिंग चालक गणेश नेपाली की दर्दनाक मौत के बाद हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नगर निगम पुलिस के साथ हाकिम विवाद होने के बाद पीड़ित गणेश ने मानसिक अवसाद में आकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोप है कि ट्रैफिक चालान और पुलिस की कथित कार्रवाई से तंग आकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया था। इस घटना के बाद से पूरे देश के युवाओं में आक्रोश फैल गया है। आंदोलन के उग्र होने का दूसरा बड़ा कारण काटमांडू में झुग्री बस्तियों को हटाने का प्रशासनिक अभियान है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था किए, नदियों के किनारे रह रहे गरीब लोगों की झुगियां जबरन हटा दीं, जिससे हजारों गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। इसके अलावा, सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, अत्यधिक बल प्रयोग और हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोपों से हालात और उग्र हो गए। विभिन्न युवा संगठनों के लोग दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर आ डटे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन शाह के कामकाज पर असंतोष जताया है। पार्टी के पहले महाधिवेशन के बाद आंतरिक मतभेद सतह पर आने लगे हैं।

वजन घटाने के लिए ज्यादा कसरत करना ठीक नहीं



हृदय (दिल) हमारे शरीर का अहम अंग है। छाती के मध्य से थोड़ी बायीं ओर स्थित दिल पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। दिल को ऑक्सीजन कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान की जाती है जो कि रक्त के माध्यम से मिलती है। अलग-अलग कारणों

की वजह से दिल में कई प्रकार की बीमारी जैसे रुमेटिक हृदय रोग, जन्मजात खराबियां, हृदय की विफलता तथा पेरिकार्डियल बहाव, कोरोनरी धमनी रोग, हार्ट अटैक, हार्ट वाल्व रोग, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक आदि हो सकते हैं।

दिल व इसीजी के आकार में स्ट्रेटोस्कोप
हृदय रोग (कार्डियोस्कुलर हार्ट डिजीज) होने का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि। यदि हाइ डेन्सिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) की मात्रा है तो वे कम प्रभावशाली होते हैं। एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह हृदय की रक्तवाहिनियों से कोलेस्ट्रॉल को बाहर लाता है। यदि लो डेन्सिटी लिपोप्रोटीन अणुओं का आकार छोटा है तो उनके रक्तवाहिनियों में जमने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापा भी दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण है। वजन घटाने के लिए नियमित व्यायाम तथा साधारण तथा संतुलित भोजन करना चाहिए।

वजन घटाने के लिए भूखे रहना और ज्यादा कसरत करना भी ठीक नहीं है, इससे दिल पर बुरा असर पड़ता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और सुबह या शाम के समय चहलकदमी करनी चाहिए। व्यायाम से हाथ-पैरों की धमनियां स्वस्थ रहती हैं जिससे शरीर में रक्त बहाव ठीक से होता है। धूम्रपान भी दिल के रोग का एक प्रमुख कारण है। सोया प्रोटीन लेने से शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, इसे गुड़ कोलेस्ट्रॉल माना जाता है।

इस तरह करें उपचार
जीवनशैली में ठरें सकारात्मक बदलाव: कार्डियोस्कुलर रोगों से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव व सुधार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि शारीरिक सक्रियता को बनाए रखा जाए। जितना हो सके तनाव से बचे। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आशावादी बनें। तनाव से बचने के लिए मनपसन्द संगीत सुन सकते हैं।

नियमित व्यायाम: नियमित रूप से व्यायाम करके आसानी से जानलेवा हृदय रोग से बचा जा सकता है। सुबह सैर पर जा सकते हैं या घर, पार्क या बागीचे में कसरत या योगा कर सकते हैं। अगर आप के परिवार में पूर्व में किसी को हृदय रोग रहा हो तो शारीरिक श्रम से आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

सर्जरी का सहारा: यदि दवाएं और नियमित देखभाल हृदय रोग के लक्षणों को कम नहीं करती हैं, तो आप सर्जरी के विकल्प के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अनेक प्रक्रियाएं जैसे हार्ट वॉल्व सर्जरी, इन्फ्रेक्ट एक्सवेलुजन सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट (हृदय प्रत्यारोपण) तथा बाईपास सर्जरी आदि संकीर्ण या अवरुद्ध धमनियों को फिर से खोलने या सीधे हृदय की विकिरा के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं।

खान पान का ध्यान रखें: तला-भुना अधिक न खाएं। फास्ट फूड और चिकनाई वाला खाना खाने से वजन भी बढ़ता है और यह चिकनाई रक्त धमनियों में जम जाती है। जिससे खून का बहार धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसलिए संतुलित व पौष्टिक आहार ही लें। फल व सब्जियों का सेवन करें।



अगर आप शराब छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि शराब लंबे समय तक आपको इफेक्ट कर सकती है। हाल ही में आई एक रिसर्च कुछ ऐसा ही कह रही है। जनरल ऑफ स्टडीज ऑन एल्कोहल एंड ड्रग्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शराब को छोड़ने के बाद भी इसका प्रभाव लंबे समय पर शरीर पर साइलेंट तरीके से रहता है। यह हेल्थ को प्रभावित करता है यानी शराब की वजह से कई तरह की परमानेंट इंजरी हो जाती हैं जिसकी वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। रिसर्च के नतीजों में पाया गया कि जो लोग युवावस्था में शराब पर निर्भर थे लेकिन शराब छोड़ने के 5 साल बाद तक उसका असर उन्हें दिखाई दिया और 60 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बेशक कम लेकिन शराब का मेंटल और फीजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट दिखा।



रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो लोग डिप्रेशन का भी खतरा



छोटी मात्रा भी खतरनाक
शराब की छोटी सी मात्रा भी शरीर को प्रभावित करती है। यह तेजी से हमारे शरीर के खून में मिल जाती है और पानी की कमी कर देती है। शराब हमारे शरीर को भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान करती है। यह हमारे उत्सर्जन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है जिसका काम होता है हमारे शरीर में मू्रमार्ग और मलमार्ग के द्वारा अवशोषित पदार्थों को बाहर करना। अधिक मात्रा में शराब के सेवन से अग्न्याशय ग्रंथि में जहरीले पदार्थ बनते हैं जिसकी वजह से उसके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है।

सायुतंत्र पर असर
सबसे अधिक एल्कोहल साइड इफेक्ट होता है हमारे लिवर पर और अधिक मात्रा में शराब के सेवन से लीवर में एल्कोहल हेपेटाइटिस हो सकता है। शराब का प्रभाव हमारे शरीर पर जल्दी ही दिखाई देने लगता है क्योंकि यह हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंच सकती है जिसकी वजह से हमारे स्नायुतंत्र पर इसका असर होता है और इसके सेवन के बाद किसी से बात करना, अधिक पीने पर खड़े रहना तक मुश्किल हो जाता है। साथ ही दिमाग के लिए भी यह हानिकारक होता है और लंबे समय तक शराब के सेवन से कई तरह की परमानेंट दिमागी समस्याएं हो सकती हैं जिनमें मतिभ्रम भी शामिल है।



कई बार घंटों लगातार बैठे रहने से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल और खान-पान में पोषक तत्वों की कमी से भी कमर दर्द की परेशानी होना आम बात है। इस दर्द के कारण बैठने-उठने में परेशानी और काम करने में भी दिक्कत आने लगती है। सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह दर्द बढ़ने लगता है। आज हम

आपको कुछ घरेलू उपाय बताते जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप दर्द से राहत पा सकते हैं।

कमर दर्द के घरेलू उपाय
अजवाइन : कमर में दर्द है तो एक छोटा चम्मच अजवाइन लेकर तवे पर सेंक लें। जब यह ठंडी हो जाए तो इसे धीरे-धीरे चबाते हुए निगलें। 7 दिन लगातार इसका

सेवन करने से दर्द से राहत मिलती है।

सिकाई : दर्द होने पर उस जगह पर पानी की सिकाई करें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो। इसके साथ ही बासी खाने से परहेज करें।

सैर भी जरूरी
सुबह सैर करने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। कमर दर्द से बचने के लिए

रोजाना सुबह 2 मील सैर जरूर करें।

सरसों का तेल : सरसों के तेल में लहसुन की तीन-चार कलियां डालकर गर्म कर लें और ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें।

कैल्शियम : कैल्शियम का कमी भी कमर में दर्द होने लगता है। ऐसे में अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त आहार को शामिल करें।

अच्छी-अच्छी चीजें हाथ लग जाती हैं। तब हर साइज और कलर में सामान उपलब्ध होते हैं और स्टॉक्स सीमित होने की चिंता नहीं रहती। हां, अगर ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहती हैं तो इसके लिए आखिरी के दो दिन सबसे मुफीद हैं। आखिरी के दो दिनों में 70प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलने लगते हैं।

» सेल के सीजन में स्टैंडर्ड साइज का अभाव होता है। मीडियम साइज के कपड़े जल्दी बिक जाते हैं। जाहिर है कि आप छोटे साइज के कपड़े तो नहीं लेंगे। इसलिए, अगर थोड़ी बड़ी साइज के मिल जाएं तो ले लीजिए क्योंकि अल्टर करवाने का ऑप्शन आपके पास होता है।

कुछ यूं गुलाब से ही पाएं गुलाब सी निखरी और कोमल त्वचा...

गुलाब, कभी प्यार तो कभी खुबसूरती को बयां करने वाला एक फूल. गुलाब, कभी हमें नर्म अहसास कराता है, तो कभी अपनी खुशबू से मन को प्रफुल्लित कर देता है. खुबसूरती के लिए भी इसकी खूब प्रतिमाएं दी जाती हैं. यही गुलाब खुबसूरती को बढ़ाने में भी मददगार है. जी हां, गुलाब न सिर्फ अपनी खुशबू से मन को सुकून पहुंचाते हैं, बल्कि ये त्वचा में नमी भी बनाए रखते हैं और चेहरे पर निखार लाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि गुलाब की पंखुड़ियों के कई फायदे हैं. गुलाब के इस्तेमाल से खुबसूरत त्वचा पाने के कुछ टिप्स-

» पानी में मिली गुलाब की पंखुड़ियों का सत्व या गुलाब जल त्वचा को नमी प्रदान करता है और ताजगी देता हैं. यह त्वचा में ऑयल को नियंत्रित करता है और पीएच बैलेंस बनाए रखता है. विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण गुलाब से बना एसेन्शल ऑयल त्वचा के रखपन को दूर करता है और निखार लाता है.

» गुलाब जल और नींबू के रस से बना टॉनिक चेहरे पर लगाने से कील, मुंहासे कम होते हैं. चेहरे पर इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. यह सामान्य और तैलीय त्वचा दोनों के लिए उपयुक्त है.

» नियमित रूप से इस्तेमाल के लिए कॉटन बॉल या रूई के फाहे को गुलाब जल में भिगोकर



इससे चेहरा साफ करें. यह प्राकृतिक टोनर का काम करता है. ऐसा आप सुबह और रात में सोने जाने से पहले कर सकती हैं. पानी में गुलाब जल डालकर आप स्नान भी कर सकती हैं, इससे चेहरे पर चमक आती है और इसकी सौम्य खुशबू से मानसिक



तनाव व शारीरिक थकावत की दूर होती है.

» गुलाब जल आंखों को स्वस्थ रखता है. इसमें मौजूद एंटी-सेप्टिक और जीवाणुरोधी गुण आंखों को धूल, गंदगी, लालिमा और मेकअप उत्पादों के केमिकल से होने वाले नुकसान से

बचाते हैं. दूध के साथ मिलाकर लगाने से यह आंखों के काले घेरे को भी दूर करता है.

» शैम्पू के दौरान नियमित रूप से गुलाब जल का इस्तेमाल बालों में नमी बनाए रखता है और कंडीशन करता है.

» बाल धोने से 10 मिनट पहले गुलाब जल और जोजोबा ऑयल को मिलाकर लगाने से यह हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से रूखे व बेजान हुए बालों को रिपेयर करता है.

» उलझे व रूखे बालों से छुटकारा पाने के लिए आप गुलाब जल और एलोवेरा को समान मात्रा में मिलाकर स्कैल्प पर अच्छे से लगा लें और 30 मिनट तक लगाए रहने के बाद धो लें.

» गुलाब में जीवाणुरोधी, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होने के कारण यह खरोंच लगी या जली त्वचा पर भी लगाया जा सकता है. इसका इस्तेमाल बुखार और खांसी में भी किया जा सकता है.

» गुलाब का खुशबू तनाव को दूर कर मूड तरोताजा करता है. यह उत्तेजना, चिंता को दूर कर राहत व सुकून का अहसास कराता है.

* गुलाब दूरियों को दूर कर त्वचा में कसाव लाकर जवां लुफ देता है. रोजहिय सीड ऑयल का इस्तेमाल करें, जो विटामिन सी, तेल और प्रोटीन से समृद्ध होता है।

खाना खजाना
एप्पल रबड़ी
 सामग्री
 3 कप वसा भरपुर दूध 2 1/2 टेबल-स्पून शक्कर 3/4 कप छिले और कसे हुए सेब 3 टेबल-स्पून हल्के उबाले और स्लाईस्ड बादाम, 1/2 टी-स्पून इलायची पाउडर

पनीर पाव भाजी
 सामग्री
 1 टेबलस्पून तेल, 100 ग्राम प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम शिमला मिर्च, 160 ग्राम टमाटर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला , 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 50 ग्राम फूलगोभी(उबली हुई), 50 ग्राम गाजर(उबली हुई), 500 ग्राम आलू(उबली हुई), 100 ग्राम पनीर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 30 ग्राम बटर, 2 टीस्पून नींबू का रस, 2 टीस्पून हरी मिर्च, 250 मिली पानी
 विधि
 1. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाल कर गर्म कर लें। अब इसमें 100 ग्राम प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 100 ग्राम शिमला मिर्च डालकर 2-3 मिनट के लिए भुनें। इसमें 160 ग्राम टमाटर डालकर भुनें और फिर इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं और पकाएं। पकने पर इसमें 50 ग्राम फूलगोभी(उबली हुई), 500 ग्राम गाजर(उबली हुई), 500 ग्राम आलू(उबली हुई), 100 ग्राम पनीर और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिलाएं करें। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 30 ग्राम बटर, 2 टीस्पून नींबू का रस, 2 टीस्पून हरी मिर्च और 250 मिली पानी डालकर 10 मिनट के लिए पकाएं। पनीर पाव भाजी तैयार है। इसे पाव के साथ सर्व करें।

रक्तमें यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की हरी झंडी



भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत युनिफॉर्म सिविल कोड बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. अब यह ड्राफ्ट आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 को पूरे दिल से और सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने सम्मानित कैबिनेट सहयोगियों और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं. हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि बिल 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के लिए तैयार हो. हमारे लिए, समानता हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का एक अहम हिस्सा रही है.उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्ट बिल समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर तैयार किया गया था और समाज के ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया है।

अभिषेक को राहत, दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन पर रोक



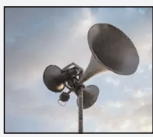
कोलकाता।तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को रविवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही सभी पक्षों को अगले आदेश या अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा. यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर आया, जिसे अभिषेक बनर्जी को कंपनी लीफ्ट एंड बांडइंस ने हाई कोर्ट में दायर किया था.कंपनी ने दावा किया कि कार्यालय जिस जमीन पर बना है, उसके वैध दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद बुलडोजर चलाया गया. मामले की तत्काल सुनवाई न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने की. कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राज्य में सियासी घमासान भी तेज हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विवाद हाई कोर्ट में लंबित होने के बावजूद बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कार्यालय को ध्वस्त किया गया।

पहले राहुल-अखिलेश को बुलाएं, फिर फड़णवीस को दें न्योता



मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया. शिंदे ने कहा कि जो लोग कभी रामभक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे और जिन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, वे आज भगवान राम और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं. दरअसल, उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी के खिलाफ राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है, जिस पर पलटवार करते हुए शिंदे ने ठाकरे के हिंदुत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं. शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने नागपुर में उद्धव ठाकरे के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व, वीर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का विरोध किया है. ऐसे लोगों के साथ जाकर उद्धव पहले ही हिंदुत्व का रास्ता छोड़ चुके हैं।

हरिद्वार में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए 94 लाउडस्पीकर



देहरादून। हरिद्वार में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. यहां धार्मिक स्थलों से 94 लाउडस्पीकर हटा दिए गए. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान ये लाउडस्पीकर तय सीमा से ज्यादा आवाज में चल रहे थे, जो ध्वनि प्रदूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन था. एजेंसी के अनुसार, इस अभियान में पुलिस की टीमों ने जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों का जायजा लिया. इस दौरान जहां भी नियमों का उल्लंघन मिला, वहां कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान शहरी क्षेत्रों से 31 और ग्रामीण इलाकों से 63 लाउडस्पीकर हटाए गए. यानी पूरे जिले में कुल 94 लाउडस्पीकर उतार दिए गए.पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है. इसलिए धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और संबंधित समितियों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई।

कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम



जम्मू। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते बड़ा आतंकी खतरा टल गया है. उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार शाम एक बड़े सचें ऑपरेशन के दौरान 4 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया है. आतंकीयों ने इस खतरनाक आईईडी को एक प्रेशर कुकर के भीतर छिपाकर सेब के बागों में प्लांट किया था, जिसे समय रहते ढूँढ निकाला गया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने बिना कोई नुकसान होने दिए इस विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है. सुरक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बांदीपोरा के मंगनीपोरा गांव के बागों में आतंकीयों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एक खुफिया इनपुट मिला था. इसके तुरंत बाद सेना की 27 असम राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर एक सैन्य तलाशी अभियान शुरू किया.इसी सचें ऑपरेशन के दौरान जवानों की नजर बाग में छिपे एक संदिग्ध प्रेशर कुकर पर पड़ी. जब जांच की गई, तो उसके भीतर 4 किलो का बेहद शक्तिशाली आईईडी बरामद हुआ।

स्काईस्क्रूट की स्पेस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज

मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के स्पेस स्टार्टअप स्काईस्क्रूट एयरोस्पेस के सफल रॉकेट लॉन्च की सराहना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से तीखा तंज कसा। कंपनी की युवा टीम की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने वाले इन इनोवेटर्स की औसत उम्र महज 28 साल है, न कि किसी 56 साल के युवा की। पीएम मोदी के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में सीधे तौर पर राहुल गांधी की ओर किया गया इशारा माना जा रहा है।

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने विज्ञान, इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की छलांग और युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। स्काईस्क्रूट एयरोस्पेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नए स्वर्णिम सफर का आगाज किया है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि इस स्काईस्क्रूट स्टार्टअप में काम करने वाली पूरी टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। यह कारनामा देश के असली युवाओं ने कर दिखाया है... मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं।

यह टिप्पणी उन्होंने संसद के मौनसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान की। इस दौरान उन्होंने विज्ञान, इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती कामयाबियों की तारीफ की और देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।

स्काईस्क्रूट एयरोस्पेस की हालिया



कामयाबी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत की युवा पीढ़ी की ऊर्जा और उम्मीदों को दिखाती है। उन्होंने कहा, भारत के युवाओं ने स्पेस में एक नए सफर की शुरुआत की है। मुझे बताया गया कि स्काईस्क्रूट स्टार्टअप में काम करने वाली पूरी टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। ऐसे ही युवाओं ने यह कारनामा कर दिखाया है। मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर परोक्ष इशारा माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ समय में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनसे वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। उनके मुताबिक, भारत की सफलताएँ सिर्फ घरेलू विकास तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच और स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी देश की स्थिति को मजबूत किया है। पिछले साल मौनसून सत्र से ठीक पहले, एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचा। और हाल ही में, एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसे प्राइवेट उद्यम देखने को मिले हैं;

भारत के युवा अंतरिक्ष में एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। यह एक जबरदस्त कामयाबी है... भारत की ग्लोबल पहचान को दुनिया भर में मान्यता और स्वीकार्यता मिल रही है। यह कोई इतोफाक नहीं है; यह एक संदेश है, एक मजबूत संदेश कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उम्मीदें अंतरिक्ष की तरह ही असीम हैं, पीएम मोदी ने कहा।

संसद के मौनसून सत्र के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि कार्यवाही रचनात्मक और नतीजे देने वाली होगी। बारिश के मौसम से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि मौनसून और संसदीय सत्र, दोनों ही तब फायदेमंद होते हैं जब वे ठीक से काम करते हैं।

चाहे मौनसून हो या मौनसून सत्र – अगर दोनों सक्रिय हों, तो वे बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। और जब दोनों फायदेमंद होते हैं, तो इससे देश का कल्याण और सभी जीवों का भला होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मौनसून सक्रिय और फायदेमंद बना रहे, और मौनसून सत्र भी फायदेमंद साबित हो।

स्काईस्क्रूट एयरोस्पेस के सफल रॉकेट लॉन्च को भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक और अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। यह उपलब्धि प्राइवेट भागीदारी के लिए सेक्टर खुलने के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जोर दिया कि भारत के युवा इनोवेशन को आगे बढ़ाने और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सेंसेक्स 443 अंक टूटा निफ्टी 24,239 पर बंद

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही है : युवराज सिंह

नईदिल्ली। भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड दौर पर टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बड़ा बयान दिया है। युवराज का मानना है कि भारतीय टीम इस समय बदलाव (ट्रॉजिशन) के दौर से गुजर रही

है, इसलिए उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब टीम को आत्ममंथन कर मजबूत वापसी करनी होगी। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ तीन मैचों की सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी। इससे पहले टी20 सीरीज में भी टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

मीडिया से बातचीत में युवराज सिंह ने टीम चयन और रणनीति को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब टीम लगातार हारती है तो हर फैसले पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होतीं तो आप तेज गेंदबाज खिलाने और स्पिनर खिलाने के बीच उलझ जाते हैं। कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को खिलाना अच्छा होता, लेकिन आखिर में फैसला टीम मैनेजमेंट का होता है।% तीसरे वनडे में भारत ने बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में जगह नहीं दी थी, जिसके बाद टीम चयन पर काफी सवाल उठे। युवराज ने कहा कि खराब प्रदर्शन के बाद आलोचना होना स्वाभाविक है और खिलाड़ियों को इसे स्वीकार करना चाहिए।

आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लगातार दो टी20 विश्व कप जीते और अब लगातार छह टी20 मैच हार गए। क्रिकेट हर किसी को जमीन पर लाने का काम करता है। कोई भी खिलाड़ी या टीम खेल से बड़ी नहीं होती। हमें इसे समझना होगा और आलोचना को स्वीकार करना होगा। 2011 विश्व कप विजेता युवराज सिंह ने कहा कि मौजूदा कठिन दौर के बावजूद लोगों को पिछले कुछ वर्षों में टीम इंडिया की उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए।

ज्योति भास्कर

देश के पहले स्वदेशी निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण, जिसे स्काईस्क्रूट नामक एक निजी कंपनी ने तैयार किया, भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक मील का पत्थर तो है ही, ऐसा करके भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास यह क्षमता मौजूद है।

दरअसल, यह ऐतिहासिक छलांग इसलिए संभव हो पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया। उस एक फैसले ने अंतरिक्ष क्षेत्र की तस्वीर बदलकर रख दी। दरअसल 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए विक्रम-1 को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसे मांग के अनुसार कभी भी बेहद कम लागत में तेजी से

लॉन्च किया जा सकता है।

जाहिर है, यह क्षमता भारत को छोटे उपग्रहों के वैश्विक बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। इससे भारत की वैश्विक बाजार पर पकड़ मजबूत होगी और दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की साख और बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल के तौर पर इस रॉकेट में, पूरी तरह से कार्बन-कंपोजिट संरचना, 3डी-प्रिंटेड इंजन और स्काईस्क्रूट द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग किया गया है और इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जो अंतरिक्ष में रॉकेट को अपना रास्ता खुद तय करने में सक्षम बनाता है।

इसरो के साथ-साथ निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में आने से भारत की तेजी से बढ़ रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। इससे अनुसंधान, इंजीनियरिंग और

प्री-आईपीओ कंपनियों में निवेश का बढ़ रहा ट्रेंड

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की उम्मीद के बीच रिटेल निवेशकों का रुझान अब तेजी से प्री-आईपीओ कंपनियों की ओर बढ़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छे आईपीओ में सीमित आवंटन मिलने के कारण निवेशक अब उन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जो अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुई हैं। पहले यह सुविधा केवल संस्थागत और हाई नेटवर्थ निवेशकों तक सीमित थी लेकिन अब अधिकृत प्लेटफॉर्म और नियामकीय व्यवस्था के चलते रिटेल निवेशकों के लिए भी यह विकल्प उपलब्ध हो गया है। प्री-आईपीओ निवेश का मतलब है किसी कंपनी के शेयर उसके शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले खरीदना। इससे निवेशकों को कंपनी की शुरुआती विकास यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।

निजी निवेश बढ़कर 9 प्रतिशत विकास दर संभव

नईदिल्ली। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन का मानना है कि भारत अपनी मौजूदा 7 फीसदी की आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 8-9% के स्तर तक ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। भारत ने पिछले वर्षों में मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता तो हासिल कर ली है, लेकिन अब समय 'संस्थागत सुधारों' का है। उन्होंने कहा कि देश को अब न्यायपालिका, नौकरशाही और फैक्टर मार्केट (जमीन, श्रम और पूंजी) में बड़े सुधार करने की जरूरत है, ताकि व्यापार करने की लागत कम किया जा सके। सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की तेज विकास यात्रा में निजी निवेश हमेशा से मुख्य चालक रहा है। एक समय था जब भारत की जीडीपी में निजी निवेश की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक थी, जो आज घटकर 22-23 फीसदी के आसपास रह गई है। इस निवेश अंतर को पाटना ही विकास दर को 9 फीसदी तक ले जाने की कुंजी है।

एलएंडटी को धातु एवं खनन क्षेत्र में मिले ठेके

नई दिल्ली। अवसरंचना क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों समेत देश की प्रमुख धातु एवं खनन कंपनियों से कई ठेके मिले हैं। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसकी धातु एवं खनिज (एमएंडएम) कारोबार इकाई को मिले इन बड़े ठेकों का मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए के बीच है। कंपनी ने निवेश के अनुसार, कंपनी को पहला ठेका सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी से मिला है। यह लौह अयस्क उत्पादक कंपनी वर्ष 2030 तक अपनी लौह अयस्क उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10 करोड़ टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) करने के लिए विस्तार कर रही है। दूसरा ठेका सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य नवरत्न कंपनी से मिला है।

पहले स्वदेशी निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की सफलता मील का पत्थर



तकनीकी क्षेत्रों में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अब तीन सौ से अधिक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो उन दर्जनों

विकासशील देशों के लिए पसंदीदा प्रक्षेपण साझेदार भी बन सकते हैं, जो कृषि आंकड़ों, आपदा निगरानी और संचार के लिए उपग्रह पहुंच चाहते हैं।

जब केवल एक व्यावसायिक अवसर नहीं

है। यह भू-राजनीतिक अवसर भी है, और विक्रम-1 की यह सफलता दर्शाती है कि भारत अब इसे जल्दी हासिल करने की स्थिति में है। भले ही भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 8.4 अरब डॉलर की है, जो कुल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग दो प्रतिशत ही है, लेकिन सरकारी अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

हालांकि स्काईस्क्रूट नामक जिस निजी कंपनी ने विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया, उसके सामने वैश्विक बाजार में स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों और बीमाकर्ताओं का भरोसा जीतने की चुनौती होगी, लेकिन फिलहाल इस प्रक्षेपण ने देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन : मुख्यमंत्री

रायपुर।गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशव्यापी 'मेरा परिवार गौरवित परिवार' अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट



प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण समृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में गाय के वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा अत्यंत सराहनीय पहल है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते

हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के स्कूलों एवं महाविद्यालयों के 1 लाख 64 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता यह दर्शाती है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि वे समाज में गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रभावी दूत बनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा

कि गौ संरक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने परिवारों और आसपास के लोगों को गौसेवा एवं गौ संरक्षण के प्रति जागरूक करें तथा इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नए शिक्षा सत्र के साथ प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव और न्योता भोज जैसी अभिनव पहल संचालित की जा रही हैं।

जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ अथवा माता-पिता की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर विद्यालयों में बच्चों के साथ भोजन कराने की परंपरा समाज और विद्यालय के बीच आत्मीय संबंध मजबूत कर रही है। इससे बच्चों को अतिरिक्त पोषण भी प्राप्त हो रहा है तथा समाज की भागीदारी भी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गाय से प्राप्त दूध, दही, गोबर और गोमूत्र सहित प्रत्येक उत्पाद मानव जीवन के लिए उपयोगी है। आज गोबर से अनेक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गोबर एवं गोमूत्र आधारित उत्पादों के निर्माण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गौपालन आय का सशक्त माध्यम बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन

के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में प्रति गाय चारे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। साथ ही सुरभि गौधाम योजना के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं से युक्त गौधाम विकसित किए जा रहे हैं, जहां पशु चिकित्सक, चरवाहे तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त होने के साथ अब विकास का नया दौर प्रारंभ हुआ है। कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से देसी गाय उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यूसीसी आदिवासियों के हितों, अधिकारों पर

डाका डालने की कोशिश : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के खिलाफ है, राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले



है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है।

जब से बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा हुई है उसके बाद से ही भाजपा के समर्थित उद्योगपति बस्तर में आदिवासियों की जमीन पर नजरे गड़ाये हुए है। बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है। राज्य के आदिवासियों के हितों को दखिनाकर करके उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश है। आदिवासियों की

जमीनें कानून दूसरा कोई ले नहीं सकता, इसलिए तमाम तरीके के रास्ते खोजने की शुरूआत की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश का मुखिया एक आदिवासी है उसके बाद राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों के हितों के खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री और सरकार ये बताये कि- क्या यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा ?पांचवी अनुसूची की पंचायतों के अधिकारों में कोई छोड़छाड़ नहीं होगी ?राज्य की संरक्षित जनजातियां बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुजिया, पांडा को संविधान में विशेष संरक्षण मिला है।

बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा बेनकाब : भूपेश

■ बातचीत की जगह आंदोलन कर रहे छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन, वंदे मातरम् को लेकर प्रस्तावित नए नियम और टीएस सिंहदेव के उनके निवास पहुंचने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को लेकर सरकार को घेरा। छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि संसद की शुरुआत और सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा सामने आ गया है। आंदोलन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद निंदनीय है।

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार चाहती तो छात्रों को



बुलाकर बातचीत कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलती का खामियाजा 22 लाख युवाओं को भुगतना पड़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में 22 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी सरकार पर है।

वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों पर भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे मातरम् आजादी के आंदोलन का प्रतीक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम् गाने वालों को अंग्रेज जेल में डाल देते थे। बघेल

ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उस समय ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और बताते थे कि कौन वंदे मातरम् गा रहा है और सजा दिलवाते थे, लेकिन आज बड़े भक्त बनने का दावा कर रहे हैं।

टीएस सिंहदेव के घर पहुंचने पर बीजेपी को दिया जवाब

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के भूपेश बघेल के निवास पहुंचने पर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेहद बेचैन है। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के बजाय सरकार ने ऐसा व्यवहार किया जैसे प्रस्ताव उनके खिलाफ हो। बघेल ने कहा कि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल पर चर्चा कर रही है।

मुख्य सचिव ने डैशबोर्ड स्कोर में सुधार के दिए कड़े निर्देश



■ गृह विभाग की राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंव सिस्टम संबंधी बैठक ली

रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं को चिह्नित कर उनमें त्वरित सुधार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से मौजूद थे।

बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ की 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। हालांकि राज्य ने 'प्रशासनिक सुधार' और 'मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल' के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्ण अंक हासिल किए हैं।मुख्य सचिव विकास शील ने

शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव: मंत्री टंकराम वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश ही एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की सच्ची नींव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। राज्य के विद्यालयों में छात्रों को भारतीय ज्ञान-परंपरा, नैतिक मूल्यों और अनुशासन से जोड़ने के लिए शालाओं में प्रार्थना, सरस्वती वंदना और श्लोक का समावेश किया गया है। उन्होंने बलीदाबाजार विधानसभा ?क्षेत्र के 11 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण हेतु 3 करोड़ की राशि स्वीकृत रायपुर जिले के तिवदा विकासखंड के शासकीय बीएनबी हायर सेकेंडरी स्कूल में विकासखंड स्तरीय शालेय प्रवेश उत्सव उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।



छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आम आदमी पार्टी आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी माननीय श्री मुकेश अहलावत जी के निर्देशानुसार आज 20 जुलाई 2026 (सोमवार) को आम आदमी पार्टी (क) द्वारा राज्य के अनेक जिलों में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। रायपुर में युवाओं द्वारा जारी अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन में आप नेताओं ने जाकर समर्थन दिया। आप द्वारा जिलों में प्रदर्शन प्रसिद्ध शिक्षाविद व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की दिल्ली में हुई हिरासत/अस्पताल में जबरन शिफ्टिंग और देश के युवाओं व बेरोजगार छात्रों के समर्थन में किया गया। प्रदर्शन के संबंध में आम आदमी पार्टी के प् नेताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलेते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में लगातार हो रहे पसर लीक और घोटालों के कारण देश में शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले रहे हैं।

21 से 30 जुलाई तक 10 दिवस के लिए पुनः खुलेगा पंजीयन पोर्टल

रायपुर। शहर में ई-रिक्षा एवं ऑटो परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा संचालित विशेष ई-रिक्षा एवं ऑटो पंजीयन एवं ऋकोड अभियान को वाहन चालकों का अच्छ सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभियान के अंतर्गत अब तक 15,047 ई-रिक्षा एवं ऑटो का सफलतापूर्वक पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 12,337 वाहनों में ऋकोड भी लगाए जा चुके हैं, जिससे वाहन एवं चालक की जानकारी तत्काल उपलब्ध होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। अब तक पंजीयन करा चुके ई रिक्षा एवं ऑटो में यातायात पुलिस द्वारा यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर में प्रतिदिन ऋकोड लगाने का कार्य निरंतर जारी है। इसके बावजूद कुछ ई-रिक्षा एवं ऑटो चालक शहर से बाहर होने अथवा अन्य कारणों से अब तक अपना पंजीयन नहीं करा सके हैं।इस संबंध में ई-रिक्षा एवं ऑटो संध के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा शेष चालकों को अवसर प्रदान करने का अनुरोध किए जाने पर डीसीपी यातायात डॉक्टर अर्चना झा ने जनहित एवं वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए *21 जुलाई से 30 जुलाई तक 10 दिवस के लिए पंजीयन पोर्टल पुनः खोलने* के निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह शेष ई-रिक्षा एवं ऑटो चालकों के लिए अंतिम अवसर होगा।

डॉ. अजय कौशिक को मिला बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर जिले के शिक्षा प्रशासन से जुड़ा अहम फैसला लिया है। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत डॉ. अजय कौशिक को जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर में सहायक संचालक (मूल पद प्राचार्य) के रूप में पदस्थ डॉ. अजय कौशिक अपने मौजूदा दायित्वों के साथ-साथ जिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए *21 जुलाई से 30 जुलाई तक 10 दिवस के लिए पंजीयन पोर्टल पुनः खोलने* के निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह शेष ई-रिक्षा एवं ऑटो चालकों के लिए अंतिम अवसर होगा।

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और मेनोपॉज के बारे में मिली जानकारी

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की "जय हरितिमा महिला समिति के तत्वावधान में विगत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर के सभागार में "महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम" का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति की सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं वक्ता "डॉ. श्रुतिता गौर", एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी), सीनियर रेंजिडेंट, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर थीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। अपने व्याख्यान में उन्होंने "पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज , रजोनिवृत्ति, सर्वाइकल कैंसर, झट्टा तथा "स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व" पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं जागरूकता को महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला बताया।कार्यक्रम का 'ड्रेस कोड नीला' रखा गया था। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में डॉ. सुनीता रॉय ने प्रथम तथा श्रीमती क्षमा अग्रवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही आयोजित मनोरंजक खेल में "समिति की अध्यक्ष श्रीमती ममता चंदेल" एवं डॉ. सुनीता रॉय विजेता रहीं, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक आनंदमय एवं उत्साहपूर्ण बन गया।

एम्स रायपुर में पेपर लेस हुआ सिस्टम

रायपुर। एम्स रायपुर ने अब ओपीडी के मरीजों को लैब टेस्ट कराने के लिए प्रिंटेड पर्ची लेकर घूमने की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। डॉक्टर जैसे ही टेस्ट लिखेंगे, उसकी जानकारी सीधे सिस्टम में पहुंच जाएगी और मरीज सीधे डोम-1 फ्लेबोटोमी जॉन जाकर सैंपल दे सकेंगे। नई सुविधा का उद्घाटन एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक और सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने किया। यहां यह बताया जरूरी होगा कि पहले मरीज को डॉक्टर से पर्ची लेकर लैब पहुंचना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर सिस्टम में टेस्ट रिक्स्टे डालेंगे। जानकारी सीधे लैब के सिस्टम में पहुंच जाएगी।इहां रजिस्ट्रेशन के बाद बारकोड बनेंगे। फिर ब्लड या दूसरे सैंपल लिए जाएंगे। यानी पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। फ्लेबोटोमी का मतलब होता है ब्लड सैंपल लेने की प्रक्रिया। फ्लेबोटोमी जॉन यानी अस्पताल का वह सैंपल कलेक्शन सेंटर, जहां मरीजों के ब्लड और दूसरे लैब सैंपल लिए जाते हैं। डोम-1 में बच्चों के लिए अलग चाइल्ड-फ्रेंडली सैंपल कलेक्शन रूम बनाया गया है। यहां ऑडियो-वीडियो की सुविधा रहेगी ताकि ब्लड सैंपल देते समय बच्चे घबरएं नहीं। कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने कहा कि एम्स रायपुर लगातार डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रहा है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास को मिलेगी नई गति

पर्यटन मंडल की 38 वीं संचालक मंडल बैठक में बनी रणनीति

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संचालक मंडल की 38 वीं बैठक सोमवार को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड मुख्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास, वर्तमान योजनाओं की प्रगति, नई पर्यटन पहलों तथा आगामी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने की। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन (भा.प्र.से.), छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य (भा.व.से.), अवर सचिव श्रीमती रवि शर्मा, उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम



शर्मा, संस्कृति विभाग के संचालक संजय कन्नौज विभिन्न विभागों के शासकीय सदस्य तथा पर्यटन मंडल के विभिन्न शाखा प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण और हरित पहल के संकल्प के साथ हुई। प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा तथा पर्यटन सचिव डॉ. एस. भारतीदासन को पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता

व्यक्त की। वहीं, उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा ने विभिन्न विभागों के शासकीय सदस्यों का पौधा भेंट कर स्वागत किया।

बैठक के दौरान पर्यटन मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तथा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षक

किया जा रहा है। बैठक में पर्यटन मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तथा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षक

एवं सुविधायुक्त बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आगामी पर्यटन कार्यक्रमों, प्रचार-प्रसार गतिविधियों, निवेश संभावनाओं तथा पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करने तथा भविष्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने की रणनीति पर सर्वसम्मति बनी। संचालक मंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि इन निर्णयों से प्रदेश की पर्यटन पहचान और अधिक सशक्त होगी।

विद्यार्थियों को ऑनलाइन टगी से बचाव और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की दी जानकारी

रायपुर। महासमूह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) द्वारा सोमवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुन्नालान्न में पुलिस विभाग के समन्वय से टिप्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी विषय पर साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनर्स ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार तथा डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन टगी, फर्जी



लिंक, ओटीपी एवं बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, साइबर बुलिंग तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि साइबर अपराध की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने प्रतिभागियों को साइबर अपराध के बाद संभावित

नुकसान को कम करने के उपायों की जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिसका विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समाधान किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग, बागबाहरा के अधिकारियों एवं प्रशिक्षण दल का विशेष सहयोग रहा।